हिन्दी दैनिक समाचार

ट्रुथ पथ

धनबाद, बुधवार
11 मार्च 2026
वर्ष : 03 अंक : 159
पृष्ठ : 08
मूल्यः 3 /-
E-Mail:-truthpath941@gmail.com

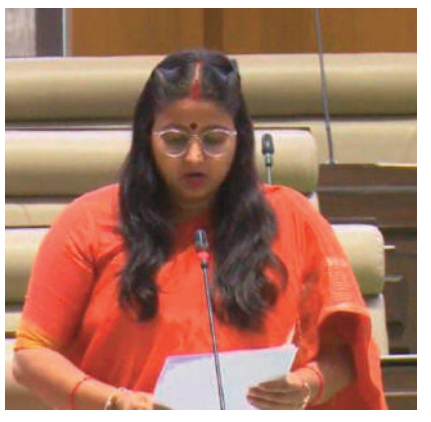

असम में निवास कर रहे आदिवासी समुदाय देश के चाय व्यापार का अभिन्न अंगः हेमन्त सोरेन

आदिवासी स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम, जारी शक्ति एवं आदिवासी काउंसिल ऑफ असम द्वारा बिस्वनाथ चारियाली स्थित मेजिकाजन चाय बागान में आयोजित जागरूकता जनसभा में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन।

असम के आदिवासी समुदाय को उनका हक-अधिकार मिले

आदिवासी समुदाय को अपना अस्तित्व और पहचान की संरक्षा के लिए एकजुट रहने की आवश्यकता

गुवाहाटी । मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज आदिवासी स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम, जारी शक्ति एवं आदिवासी काउंसिल ऑफ असम द्वारा बिस्वनाथ चारियाली स्थित मेजिकाजन चाय बागान में आयोजित एक जनसभा में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम में निवास करने वाले गरीब-गुरबा, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों पर लम्बे समय से अत्याचार एवं शोषण की बातें लगातार मैंने सुनी है। आप सभी लोगों ने यहां पर कई राजनीतिक एवं सामाजिक उतार-चढ़ाव देखे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारों वर्षों से आप सिर्फ असम नहीं बल्कि इस देश के चाय व्यापार जगत का अभिन्न अंग है। आपके बूते ही चाय उद्योग चल रहा है। असम के आदिवासी समुदाय के वैसे भाई-बहन, माता एवं बुजुर्ग जो चाय उद्योग में कार्य करते हैं उन्हें कार्य के बदले मेहनताना के रूप में क्या मिलता है यह किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि आप लोगों के हक-अधिकार की लड़ाई लड़ते-लड़ते क्रांतिकारी नेता प्रदीप नाग जी ने अपने प्राण की आहुति दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य झारखंड में भी जल, जंगल, जमीन का संरक्षण एवं आदिवासी समुदाय की पहचान तथा उनके हक-अधिकार अधिकार के लिए लम्बा संघर्ष हुआ। लगभग 50 वर्ष के संघर्ष के बावजूद जब परिणाम सकारात्मक नहीं रहा तब हमारे अग्रणी नेता दिशोम गुरु स्व० शिबू सोरेन सहित अनगिनत क्रांतिकारी नेताओं ने अलग राज्य लेने का निर्णय किया। अलग राज्य निर्माण का संकल्प उसे समय बहुत बड़ा संकल्प था। इस संकल्प को पूरा करने की शुरूआत धनबाद जिला यानी कि कोयला नगरी से प्रारंभ की गई। उस समय क्रांतिकारी नेता स्वर्गीय शक्ति नाथ महतो ने भी कहा था कि यह लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है यह बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि इस लड़ाई में शामिल पहली पंक्ति के लोग मारे जाएंगे तथा दूसरी पंक्ति के लोग जेल जाएंगे। उन्होंने कहा था कि तीसरी पंक्ति के लोग ही राज्य को सजाने-संवारने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक उसी तरह का घटनाक्रम भी हुआ। अलग झारखंड राज्य के निर्माण की लड़ाई में न जाने हमारे कितने क्रांतिकारी वीर शहीद हुए, उस संघर्ष में न जाने कितने माताओं-बहनों की मांग सुनी हुई, बच्चे अनाथ हुए। इतनी यातनाओं के बावजूद हमारे क्रांतिकारी सपूतों ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई और संघर्ष को जारी रखा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग झारखंड राज्य बनने के बाद यह दुर्भाग्य रहा की हमारे आदिवासी समुदाय के लोग आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से मजबूत नहीं बन सके। हमारी सरकार अब झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोगों को उनका हक-अधिकार देने का कार्य निरंतर कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में रहने वाले आदिवासी भाई-बहनों को यहां एक बड़े परिवर्तन की राह पर चलने की आवश्यकता है। इस परिवर्तन के लिए यह जरूरी है कि हम सभी लोगों को एक छत और एक छांव पर आना होगा। अब यहां के आदिवासी समुदाय को बौद्धिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी लोग उस समुदाय के लोग हैं जो संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटते हैं। आदिवासी समुदाय कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। किसी का शोषण या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। अब हम अपना हक-अधिकार कैसे लेंगे यह हम सभी को बिल्कुल पता है। आदिवासी समुदाय को संविधान में प्रदत्त हक-अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि यह विडंबना है कि हजारों वर्षों से असम में निवास करने वाले आदिवासी समाज के साथ आखिर भेदभाव क्यों किया जा रहा है, उन्हें आदिवासी का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। असम का एक बहुत बड़ा धड़ा कई यातनाओं से गुजर रहा है, इतना बड़ा समूह वर्तमान समय में अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्थिति को बदलने के लिए हम सभी को चट्टान की तरह एकजुट रहना पड़ेगा। पूरे देश में आदिवासी, दलित, पिछड़ों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर वह प्रयास करने की जरूरत है जो हम सभी लोग मिलजुल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के भीतर कुछ वैसी शक्तियां हैं जो आदिवासी समुदाय को आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से कमजोर करने पर कोशिश करते हैं। इस समुदाय के लोगों को मजदूर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इन सब चीजों से हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। असम एक बेहतरीन एवं खूबसूरत वादियों वाला राज्य है। पर्यटन की दिशा में इस राज्य में असीम संभावनाएं हैं।

ब्रीफ न्यूज

जिष्णु देव वर्मा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली

मुंबई, (एजेंसी) : महाराष्ट्र के नवनियुक्त राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने मंगलवार को लोकभवन में राज्यपाल पद की शपथ ली। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने लोकभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथग्रहण समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

लोकभवन में शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। वह महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल बने हैं। लोकभवन में शपथ विधि कार्यक्रम की शुरूआत राष्ट्रगान और राज्यगीत से हुई तथा समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

वाटरशैड विकास के लिए 1358.40 करोड़ रुपए स्वीकृत : केंद्रीय राज्य मंत्री

नई दिल्ली, (एजेंसी) : केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने बताया कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत वाटरशैड विकास के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान 1358.40 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए जिसमें से 1146.66 करोड़ रुपए खर्च किये गए हैं। उन्होंने यह जानकारी राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सदन में दी।

उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत हर खेत को पानी योजना के अंतर्गत 893 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए जिनमें से 743.58 करोड़ रुपए खर्च किये गए जबकि कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत 184.34 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए जिसमें से 132.63 करोड़ रुपए खर्च किये गए। उन्होंने बताया की त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत बर्ष 2025-26 के दौरान 1850 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए जिसमे में से 1189.27 करोड़ रुपए खर्च किये गए।

नापोम जरोनी में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

गुवाहाटी । तेजपुर के निकट नापोम जरोनी क्षेत्र में आयोजित इफ्तार पार्टी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन शामिल हुए। इस अवसर पर स्थानीय लोगों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।

इफ्तार के दौरान मुख्यमंत्री ने रोजेदारों के साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया और सभी को रमजान की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना भाईचारे, सहिष्णुता और

आपसी सद्भाव का संदेश देता है। समाज में एकता और आपसी प्रेम को मजबूत बनाने में ऐसे आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी ने मिलकर अमन, शांति और तरक्की की दुआ मांगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल भी जाना। इस मौके पर मंत्री चमरा लिण्डा और राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन खास तौर पर शामिल रहे।

लोकसभा में सभापति ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश

नई दिल्ली(एजेंसी) : लोकसभा में मंगलवार को विपक्षी दलों ने स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में 50 से अधिक सांसदों ने वोट किया, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने इसे सदन में पेश करने की अनुमति दे दी। प्रस्ताव पर लोकसभा में 10 घंटे तक चर्चा होना संभावित है।

विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही के संचालन में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों का कहना है कि स्पीकर की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा नहीं दिख रहा है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने यह अविश्वास प्रस्ताव लाया है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार और नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश का नेतृत्व कमजोर और बुजदिल साबित हो रहा है। गोगोई ने यह भी सवाल उठाया कि जब स्पीकर अनुपस्थित हों तो डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पीठासीन सदस्य जगदंबिका पाल किस

अधिकार से सदन की कार्यवाही चला रहे हैं।दरअसल, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद लंबे समय से खाली है। परंपरा के अनुसार यह पद आमतौर पर विपक्ष को दिया जाता रहा है। 16वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के दौरान सहयोगी दल अन्नाद्रमुक के एम. थंबीदुरई को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। हालांकि 17वीं और 18वीं लोकसभा में अब तक इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है।सदन की कार्यवाही के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नियमों का हवाला देते हुए पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। उन्होंने कहा कि जब स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो, तब स्पीकर स्वयं कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि अभी तक डिप्टी स्पीकर नियुक्त नहीं किया गया है और चेयर पर बैठे सदस्य भी स्पीकर की अनुमति से ही आए हैं, इसलिए उन्हें इस प्रस्ताव पर कार्यवाही चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने मांग की कि बहस शुरू होने से पहले सदन की सहमति से तय किया जाए कि कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करेगा।

अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा विपक्ष

नई दिल्ली,(एजेंसी) : लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद अब कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी ऐसा ही प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। विपक्षी पार्टियों के दो सीनियर नेताओं ने सोमवार को इसके संकेत दिए। जानकारी के मुताबिक ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे के बाद विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर विचार कर रहा है। अगर विपक्ष संसद में महाभियोग का नोटिस देता है, तो देश में पहली बार होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग आएगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर कांग्रेस नेता ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि एसआईआर के विरोध में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत हुई है और सभी पार्टियां

अलग-अलग राज्यों में वोटर रोल के चल रहे एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बारी-बारी से होगा।बता दें मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरुरत होती है। इसके बाद ही इससे जुड़े नोटिस को विचार के लिए स्वीकार किया जाता है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनके कार्यों से संबंधित 2023 के कानून के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से केवल उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

तेजपुर के निकट सोनितपुर में स्थानीय आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का पारंपरिक स्वागत किया

गुवाहाटी (एजेंसी) : तेजपुर के निकट सोनितपुर जिले में स्थानीय आदिवासी समाज द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य-संगीत प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंत्री चमरा लिंडा, राजमहल विधायक एम टी राजा भी मौजूद थे।

कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्रामीणों और समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत पारंपरिक पगड़ी, अंगवस्त्र और फूल-मालाओं से किया। आदिवासी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हुए पारंपरिक ढोल-नगाड़ों और लोकगीतों के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्थानीय लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा हमारी अमूल्य धरोहर है, जिसे संरक्षित और प्रोत्साहित करना हम सबकी जिम्मेदारी है।

कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज के गणमान्य लोग तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया।

संक्षिप्त खबरें

दुमका में बसों का परिचालन ठप, हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने से बस कर्मियों की अनिश्चितकालीन बंदी

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

दुमका : दुमका बस मजदूर संघ के अध्यक्ष पर हुए हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में मंगलवार से दुमका में बसों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया।बस मालिकों, चालकों और खलासियों ने संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है। इस निर्णय के बाद बस स्टैंड परिसर में सभी बसों का संचालन बंद रहा और बस कर्मी बस स्टैंड गेट पर धरना देकर बैठे रहे।बस कर्मियों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व दुमका में मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह पर हमला किया गया था, जिसमें वे घायल हो गए थे। घटना के बाद संघ की ओर से प्रशासन से हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई थी, लेकिन अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसी के विरोध में संघ के सदस्यों ने बसों का परिचालन ठप करने का फैसला लिया।बस बंदी के कारण दुमका से विभिन्न जिलों और राज्यों के लिए चलने वाली यात्री बसों का संचालन प्रभावित हुआ। सुबह से ही बस स्टैंड पर यात्री बसों का इंतजार करते रहे, लेकिन बस नहीं चलने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।कई यात्रियों को निजी वाहनों या वैकल्पिक साधनों से अपने गंतव्य तक जाना पड़ा। बस मालिकों और कर्मियों ने कहा कि जब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होती और सुरक्षा को लेकर ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक बसों का परिचालन शुरू नहीं किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और मामले को जल्द सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। बसों के ठप रहने से दुमका और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ा है।खासकर दैनिक यात्रियों, छात्रों और कामकाजी लोगों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

उद्यान महाविद्यालय जाने वाली सड़क जर्जर, मरम्मतिकरण की मांग,विस में शून्यकाल के दौरान विधायक ने उठाया मामला

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

सरायकेला : खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड के बिंज ग्राम में स्थित उद्यान महाविद्यालय तक जाने वाली सड़कों के मरम्मति कराने की मांग की है।मंगलवार को विधानसभा बजट सत्र में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाते हुए विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि उद्यान महाविद्यालय तक पहुंचने के लिये तीन अलग अलग ग्रामीण सड़कें है।वर्तमान में ये तीनों ही सड़कें जीर्ण अवस्था में है।विधायक दशरथ गागराई ने सदन के जरिये राज्य सरकार से उद्यान महाविद्यालय जाने वाली सड़कों के मरम्मतिकरण कराने की मांग की है।मालूम हो कि उद्यान विद्यालय जाने वाली सभी सड़कें जर्जर हो गयी है। लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।बरसात के मौसम में खराब सड़क के कारण आपात स्थिति में चिकित्सकीय सुविधा तक पहुंचना भी कठिन हो जाता है।यह राज्य का एकमात्र उद्यान महाविद्यालय है, लेकिन खराब सड़क वजह से बाहर से लोग यहां आने से हिचकते हैं।

चार माह से वेतन को तरस रहे एनआरएचएम कर्मी, बुधवार से कार्य बहिष्कार का ऐलान

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

पलामू : पलामू जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले एनआरएचएम कर्मियों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। पिछले चार महीनों से वेतन न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे दर्जनों कर्मचारी मंगलवार दोपहर 3 बजे पलामू समाहरणालय पहुंचे और डीसी को ज्ञापन सौंपकर आक्रोश व्यक्त किया। कर्मियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं हुआ, तो वे बुधवार 11 मार्च से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हड़ताल पर रहेंगे।प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि नवंबर 2025 से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन के अभाव में न केवल उनके हालिया पर्व-त्योहार फीके रहे, बल्कि अब घर की बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी असंभव हो गया है। कर्मियों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा बार-बार आश्वासन तो दिया गया, लेकिन फरवरी 2026 बीत जाने के बाद भी बैंक खातों में वेतन की राशि नहीं पहुंची। थका-हारकर अब सामूहिक निर्णय लिया गया है कि जब तक वेतन भुगतान की ठोस प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तब तक कोई भी कर्मचारी कार्य नहीं करेगा।

आवास योजना से जुड़े कर्मियों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

खूंटी : खूंटी मुख्यालय के सामने ग्रामीण इलाकों में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना तथा आंबेडकर आवास योजना में संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मियों ने अपनी लंबित मानदेय संबंधी मांगों को लेकर सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। राज्य आवास कर्मी संघ की ओर से ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार को पत्र भेजकर जल्द से जल्द मांगों के समाधान की मांग की गई है।राज्य आवास कर्मी संघ के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना और आंबेडकर आवास योजना के तहत कार्यरत कर्मियों का मानदेय काफी कम है। इसे देखते हुए संघ ने लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय 36 हजार रुपये तथा प्रखंड समन्वयक का मानदेय 45 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है।इसके अलावा कर्मियों के पदों की प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति देने, मासिक मानदेय को संशोधित कर ग्रेड के आधार पर निर्धारित करने, क्षेत्र भ्रमण भत्ता प्रदान करने तथा आकस्मिक परिस्थितियों में पदाधिकारियों एवं कर्मियों को विभागीय स्तर पर अपील का अवसर देने की भी मांग की गई है।राज्य आवास कर्मी संघ ने सरकार को अपने चरणबद्ध आंदोलन की भी जानकारी दी है। इसके तहत 16 फरवरी से 18 फरवरी तक काला बिल्ला लगाकर कार्य किया जाएगा, जबकि 23 फरवरी से 25 फरवरी तक कलमबंद हड़ताल की जाएगी। इसके बाद 10 मार्च 2026 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों एवं राज्य मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

संदेहास्पद स्थिति में मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

पलामू : पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव संदेहास्पद स्थिति मिलने से गांव में सनसनी फैला गया, मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के पोखरापर गांव निवासी रामबिलास पासवान के पुत्र संजय कुमार पासवान 25वर्ष के रूप में की गयी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह गांव स्थित सरकारी स्कूल के समीप एक युवक का शव देखा, शव मिलने की खबर सुनते ही घटनास्थल पर लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाना को दी, सूचना मिलते ही हुसैनाबाद पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चंदन कुमार दल बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया।पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे स्वास्थ उपाधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार रवि ने शव को देखने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम हाउस के समीप लोगो का हुजूम उमड़ पड़ा। वही एसडीपीओ एस एस मोहम्मद

याकूब पोस्टमार्टम हाउस जाकर शव को बारीकी से साथ देखा, वही मौजूद ग्रामीणों से इसकी जानकारी ली।घटना को लेकर मृतक की मां सुमित्रा देवी ने हुसैनाबाद थाना में लिखित आवेदन दिया है, जिसमें कहा है की अलीनगर गांव के मिथिलेश पासवान विमलेश पासवान, रामबली पासवान कमलेश पासवान द्वारा मेरे बेटा को पिछले तीन माह पूर्व जान मारने की धमकी दिया था। मुझे पूर्ण विश्वास है की मेरे पुत्र की इन लोगों ने हत्या कर फेंक दिया है।इस संबंध में हुसैनाबाद पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया की मृतक की मां द्वारा लिखित आवेदन थाना को दिया गया है।वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन की जा रही है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आएगी

मृतक अपने घर का इकलौत था।घटना के बाद मृतक के पिता रामविलास पासवान और मां सुमित्रा देवी वा अन्य रिश्तेदारों की चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। रामविलास पासवान ने बताया की घर का इकलौत चिराग था जिसने लोगों ने बुझा दिया।संजय कुमार पासवान सोमवार को अपने गांव पोखरापर से अपने रिश्तेदार के लड़के के साथ जपला स्टेशन आया था।रिश्तेदार ने बताया की उसको वाराणसी रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में बैठा कर वापस घर लौटे थे, लेकिन रांची नहीं बल्कि उसका शव अलीनगर कैसा पहुंचा जो एक जांच का विषय है।

एक्सएलआरआई को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस महकमे में हड़कंप, कैंपस खाली कराया गया

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

पूर्वी सिंहभूम : जमशेदपुर शहर के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान एक्सएलआरआइ को बम से उड़ाने की एक अज्ञात धमकी मिलने के बाद मंगलवार को पूरे शहर में सनसनी फैल गई।यह धमकी एक अज्ञात ई-मेल के माध्यम से भेजी गई थी। ई-मेल मिलते ही संस्थान के प्रबंधन में हड़कंप मच गया और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत इसकी सूचना पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी गई।इस संबंध में जिला प्रशासन के ओर से कुछ भी फिलहाल करने से इनकार किया गया था।एसएसपी के निर्देश पर सुरक्षा घेरे में कैंपस संस्थान के प्रमुख ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसएसपी पीयूष कुमार पांडेय से संपर्क किया और धमकी भरे ई-मेल की जानकारी साझा की। सूचना मिलते ही एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक दूबे को पूरी टीम और बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया। कुछ ही देर में पुलिस बल ने पूरे कैंपस को अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया।एहतियात के तौर पर एक्सएलआरआइ परिसर को तुरंत खाली कराया जा रहा है। क्लासरूम, हॉस्टल और प्रशासनिक भवनों से छात्रों और कर्मचारियों को बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है।आवश्यक सुरक्षा मापदंडों को अपनाते हुए पुलिस और खोजी कुत्तों (डॉग स्क्वायड) की मदद से पूरे कैंपस के चप्पे-चप्पे की सघन तलाशी ली जा रही है।पुलिस का साइबर सेल विभाग यह पता लगाने में जुट गया है कि यह धमकी भरा ई-मेल कहां से और किस आईपी एड्रेस से भेजा गया है।एसएसपी पीयूष कुमार पांडेय ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जांच पूरी होने तक कैंपस में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में उपायुक्त ने दिये निर्देश,प्रथम एएनसी से प्रसव तक करें फॉलोअप

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

लोहरदगा : उपायुक्त डॉ ताराचदं की अध्यक्षता में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को अपने-अपने पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का फॉलोअप प्रसव पूर्व जांच से प्रसव तक किये जाने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड की दवाओं का सेवन बेहद जरूरी है, इसका पालन कराएं। इससे हीमोग्लोबीन का स्तर बढ़ेगा। नियमित रूप से उसकी जांच, दवाओं का सेवन, संस्थागत प्रसव, नवजात का टीकाकरण आदि का कार्य किया जाए। किसी भी चरण में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जिन बच्चों का टीकाकरण का समय हो उनके अभिभावक को ससमय सूचित किया जाए। गर्भवती महिलाओं की नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया। एमटीसी केंद्रों में भी अतिकुपोषित बच्चों को भर्ती किया जाए ताकि उनकी बेहतर देखभाल हो सके। उन्हें अतिकुपोषित की श्रेणी से बाहर लाया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी मरीज की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है तो उसे उसके घर तक पहुंचाने में अपनी संवेदनशीलता अवश्य दिखाएं। परिजन की हरसंभव मदद करें।

उपायुक्त ने कहा कि जिन पंचायतों में एमडीए कार्यक्रम में उपलब्धि कम है वहां अभियान चला कर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा व कृमिनाशक दवा खिलाएं और छूटे हुए लोगों को भी प्रेरित करें। एक सप्ताह में इसे अभियान चला कर पूर्ण करें।उपायुक्त ने बैठक पीएम अभीम और 15वें वित्त आयोग अंतर्गत संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिये। साथ ही, जिला में कुष्ठ रोगियों की पहचान व उनका इलाज, टीबी रोगियों की पहचान व उनका इलाज के संबंध में चर्चा की गई व निदेश दिये गये।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा: मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत, पोटका के दो युवकों ने भी गंवाई जान

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

पूर्वी सिंहभूम : हरियाणा के भिवाड़ी स्थित दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सोमवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया।कापड़ियावास में सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी की एक निमार्णाधीन साइट पर खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई। इस मलबे में दबने से कुल 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिले अंतर्गत पोटका थाना क्षेत्र के पोहीत गांव के दो युवक भी शामिल हैं। इस भीषण हादसे में पोटका के पोहीत निवासी भागीरथ गोप और संजीव गोप की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।जानकारी के अनुसार, ये दोनों युवक परिवार की आर्थिक मदद के लिए कुछ समय पहले ही हरियाणा मजदूरी करने गए थे।गांव के दो होनहार युवकों की मौत की सूचना पाकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शोकाकुल

परिजनों को ढांढस बंधाने उनके घर पहुंच रहे हैं।हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल (एसडीआरएफ) ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भारी मशीनों की मदद से मलबे को हटाया गया, जिसके बाद सात शवों को बाहर निकाला गया।प्रशासन ने मृतकों की पहचान शिवशंकर, परमेश्वर मेहता, मंगल मेहता, भागीरथ गोप, सतीश, संजीव गोप और धनंजय मेहता के रूप में की है।सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल भेजा गया है। घायल मजदूरों का उपचार नजदीकी अस्पताल में चल रहा है, जिनमें से कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी बताया जा रहा है। घटनास्थल पर काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि निमार्णाधीन साइट पर मिट्टी धंसने की आशंका के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और निर्माण कंपनी के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर, पोटका के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मृतकों के पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक गांव लाने की व्यवस्था की जाए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाया जाए।

हाथी ने घर तोड़ा, दीवार गिरने से 5 माह की बच्ची की हुई दबकर मौत

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

गुमला : गुमला जिला अंतर्गत करंज थाना क्षेत्र के सरगांव पतराटोली गांव में एक जंगली हाथी ने बीते रात जमकर उत्पात मचाया।जंगली हाथी ने चंदन उरांव के घर को तोड़ दिया जिसके दीवार गिरने से पांच माह की बच्ची की दबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना बीते रात 11 बजे की बताई जा रही है।उस वक्त घर में चंदन उरांव अपनी पत्नी बच्चों के साथ सोए हुए थे। तभी गजराज ने घर में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया।चन्दन उरांव की पत्नी अपने पाँच वर्षीय बेटे को लेकर घर से बाहर भागी परंतु 5 माह की बेटी अमिता उरांव को बचा ना सकी। दीवार गिरने से बच्ची दब गई वही चंदन उरांव की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। जैसे ही घटना की जानकारी

ग्रामीणों को हुई पूरे गांव में चीख पुकार मच गई भय वश ग्रामीण रतजग्गा करने पर विवश हो गए।

घटना की सूचना जैसे ही वन विभाग बसिया को टीम को मिली करंज पुलिस से समन्वय स्थापित कर रात में ही घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली पीड़ित परिवार को तत्काल सहयोग राशि प्रदान किया।घटना की सूचना पर करंज थाना प्रभारी करण टूडू दलबल के साथ सरगांव पतरा टोली पहुंचे शव को कब्जे में लेकर अग्रतर कार्रवाई में जुट गए। डुड़िया पंचायत की मुखिया रश्मि लकड़ा एवं पूर्व मुखिया बसंत उराव पीड़ित परिवार से मिलकर मृतक के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें सन्तवना दी।

मुखिया रश्मि लकड़ा ने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है 5 माह की बच्ची की दर्दनाक मौत ने अंदर से झकझोर दिया है।वन विभाग पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान करें एवं घायल महिला का समुचित इलाज की तत्काल व्यवस्था करें। आए दिन सरगांव वन क्षेत्र में गजराज की आने की सूचना मिलती रहती है, वन विभाग की टीम जल्द जंगली हाथी को दूसरे सुरक्षित स्थान पर निकले ग्रामीणो के घर एवं फसलों को जंगली हाथी काफी नुकसान पहुंचा रहा है।

नीति आयोग अंतर्गत संपूर्णता अभियान समारोह 2.0 की शुरूआत, प्रमुख इंडिकेटर पर हुई चर्चा

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

पलामू : पलामू जिले में नीति आयोग के अंतर्गत ह्यसंपूर्णता अभियान समारोह 2.0ह्न की औपचारिक शुरूआत की गई। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विकास से जुड़े प्रमुख संकेतकों (इंडिकेटर) पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में विशेष रूप से पांच प्रमुख इंडिकेटर पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें बाल जन्म अनुपात, जन्म के समय बच्चों का वजन, टीबी बीमारी के केस नोटिफिकेशन, आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यशीलता का प्रतिशत तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति शामिल हैं। इसके साथ ही विद्यालयों में बालिका शौचालय की उपलब्धता और मवेशियों के टीकाकरण का प्रतिशत जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विस्तार से समीक्षा की गई।कार्यक्रम में उपायुक्त समीरा. एस ने बताया कि इन इंडिकेटरों में सुधार के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा पशुपालन विभाग को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया गया। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य आकांक्षी जिलों में विकास की गति को तेज करना और आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग और जनभागीदारी पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

दानुआ घाटी में भीषण हादसा अनियंत्रित ट्रेलर 60 फीट गहरी खाई में गिरा, उपचालक की मौत

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

हजारीबाग : चौपारण दानुआ घाटी के जोड़रही पुल के पास भीषण सड़क हादसा हो गया।बोकारो से बिहार की ओर जा रहा एक अनियंत्रित ट्रेलर लगभग 60 फीट गहरी खाई में जा गिरा।हादसे में ट्रेलर के उपचालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रेलर को चालक पंकज कुमार पिता बृजनंदन यादव, निवासी हखरकपुर, भोजपुर (बिहार) चला रहे थे।दुर्घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई थी। इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई।बताया जाता है कि ट्रेलर बोकारो से बिहार की ओर जा रहा था।इसी दौरान दानुआ घाटी के जोड़रही पुल के पास चालक का नियंत्रण वाहन पर से हट गया और ट्रेलर सीधे खाई में गिर पड़ा।हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।सूचना मिलते ही चौपारण पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया।

विवाह समारोह में जा रहे दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत,बाइक पेड़ से टकराई

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

साहिबगंज : जिले में देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक एक विवाह समारोह में भोज खाने जा रहे थे, तभी उनकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम का माहौल है जानकारी के अनुसार यह हादसा सोमवार देर रात करीब 12:30 बजे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभनपुर डेरा के पास हुआ। बताया जाता है कि बाइक पर सवार दो युवक तेज गति से जा रहे थे।इसी दौरान शोभनपुर डेरा के समीप बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे स्थित पीपल के पेड़ से जा टकराई।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी।सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायल अवस्था में सड़क पर पड़े दोनों युवकों को तुरंत सदर अस्पताल साहिबगंज लाया गया। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।मृतकों की पहचान सनोज कुमार यादव लगभग 20 वर्ष,पिता कुंवर यादव, निवासी तालबन्ना तथा बादल यादव लगभग 22 वर्ष, पिता देवानंद यादव, निवासी शोभनपुर भट्ठा के रूप में हुई है।दोनों युवक आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं और विवाह समारोह में भोज खाने जा रहे थे।घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक का माहौल है।सड़क हादसे की सूचना जैसे ही मिली,थाना की रात्रि गश्ती पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। घायल अवस्था में सड़क पर गिरे दोनों युवकों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है।

ट्रूथ पर्थ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक कुमार भारती के द्वारा डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, भास्कर प्रीटिंग प्रेस गोविंदपुर मेन रोड, अशोक नगर के.जी. आश्रम, धनबाद (झारखंड) से
मुद्रिक एवं नियर भाटिया शिव मंदिर, गांधी नगर धनबाद से प्रकाशित फोन नं. 7004605076, 9852421580
संपादकः- रवि रंजन * इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं सम्पादन हेतु पी आर बी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उतरदायी। ई. मेलः-truthpath941@gmail.com आर. एन. आई.नंबर .-JHAHIN/2023/90593

संक्षिप्त खबरें

बिन मौसम बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, सड़कों पर लबालब पानी, हर गली बनी झील

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : कतरास कोयलांचल में एका एक आंधी तूफान के साथ साथ काफी बारिश हुई जिससे धनबाद नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। नालों की सफाई और जलनिकासी व्यवस्था की असलियत सामने आ गई। कतरास के सब्जी पट्टी की मुख्य सड़कें जलमग्न हो गईं जिससे नदी जैसा नाजारा देखने को मिला। लोगों को घुटनों तक पानी से गुजरना पड़ा, वहीं कई जगहों पर गड्ढों में भरे पानी के कारण दुर्घटनाएं भी हुईं। आम लोग गंदे पानी में जाने को विवश थे।सब्जी पट्टी,रानी बाजार की गली पूरी तरह जलमग्न थे। जिसके कारण आवागमन ठप हो गया और जाम की स्थिति बन गयी थी।वही गंदे नाली का पानी दुकानों में घुस रहा था।सब्जी पट्टी के छोटे-मोटे दुकानदार की सब्जी पानी में डूब गई जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव आते हैं चले जाते हैं।वार्ड की स्थित अभी भी जस की तस बनी हुई है। दूसरी और भरी आधी तूफान के कारण के बड़े-बड़े पेड़ गिर गए।

सिंदरी के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए हर्ल व शिक्षा विभाग के बीच हुआ एमओयू

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : सिंदरी इलाके में मौजूद 10 सरकारी स्कूलों में शिक्षा और उससे जुड़ी संरचनाओं में सुधार व बढ़ोतरी करने तथा स्कूलों के विकास के लिए मंगलवार को हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (हर्ल) तथा जिला शिक्षा विभाग के बीच एमओयू साइन हुआ। एमओयू पर हर्ल सिंदरी के बिजनेस यूनिट हेड गौतम माजी और जिला प्रशासन की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक आयुष कुमार ने हस्ताक्षर किए।इसकी जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि इस एमओयू से सिंदरी इलाके में मौजूद 10 सरकारी स्कूलों में शिक्षा और उससे जुड़ी संरचनाओं में सुधार और बढ़ोतरी पर फोकस किया जाएगा। यह पहल हर्ल के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत की जा रही है। जो कंपनी के सस्टेनेबल सोशल अपलिफ्टमेंट के कमिटमेंट पर जोर देता है। इसमें हर्ल से राशि मिलेगी और इस प्रोजेक्ट को जमीन पर जिला प्रशासन द्वारा पूरा किया जाएगा, ताकि स्थानीय शिक्षा की गुणवत्ता और जरूरतों के हिसाब से इसे पूरा किया जा सके।

प्रिंस खान गिरोह का गुर्गा दिलीप सिंह को रिमांड पर लेगी धनबाद पुलिस

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : पिछले रविवार को धनबाद के फायरिंग रेंज में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भागने में सफल रहा प्रिंस खान का गुर्गा दिलीप सिंह को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। घटना के अगले दिन ही दिलीप सिंह की गिरफ्तारी बरवाअड्डा थाना क्षेत्र से की गई थी। एसएसपी प्रभात कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि आगेनाईज क्राइम में संलिप्त कोई भी अपराधी पुलिस से नहीं बच पाएगी, सब की कुंडली पुलिस ने तैयार कर रखी है।प्रिंस खान गिरोह के गिरफ्तार अपराधकर्मी दिलीप सिंह को धनबाद पुलिस रिमांड पर लेगी। पिछले रविवार को पुलिस मुठभेड़ के दौरान अपराधकर्मी दिलीप सिंह भागने में सफल रहा था। अगले ही दिन उसे बरवा अड्डा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया था जिसे जेल भी भेज दिया गया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस अब दिलीप सिंह को पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लेगी। बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में सुदीश ओझा नामक अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हुआ था। उसके पैर में दो गोली लगी थी। फिलहाल सुदीश पुलिस निगरानी में इलाजरत है। एसएसपी ने बताया कि सुदीश नामक अपराधी फिलहाल अस्वस्थ है। उसके पूरी तरह ठीक होने पर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। एसएसपी ने बताया कि संगठित गिरोह के अपराधकर्मियों की सूची पुलिस पहले से ही तैयार कर चुकी है। कई नए गिरफ्तारियां भी हुईं हैं उनसभी को भी सुचिबद्ध किया जा रहा है।

मानदेय और स्थायीकरण की मांग को लेकर मनरेगा कर्मचारियों का धरना

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की।धरना को संबोधित करते हुए संघ के धनबाद जिला अध्यक्ष यासीन अंसारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की संवेदनहीनता के कारण राज्य के मनरेगा कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड में कई मनरेगा कर्मियों को पिछले 6 से 12 महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।यासीन अंसारी ने कहा कि कई कर्मचारी करीब 19 वर्षों से मनरेगा योजना के तहत सेवा दे रहे हैं, इसके बावजूद अब तक उनकी सेवा को स्थायी नहीं किया गया है।कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सेवा का स्थायीकरण किया जाए और मनरेगा कोषांग के अनुरूप उन्हें ग्रेड पे का लाभ दिया जाए।उन्होंने कहा कि इन्हीं मांगों को लेकर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि राज्य सरकार जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना देने को बाध्य होंगे।

महापौर व वार्ड पार्षद 18 मार्च को करेंगे शपथ ग्रहण

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 में धनबाद नगर निगम के महापौर एवं वार्ड पार्षद तथा चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष व वार्ड पार्षद आगामी 18 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे।जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि धनबाद नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर एवं वार्ड पार्षदों के साथ 18 मार्च को 10 बजे सुबह समाहरणालय के प्रथम तल पर स्थित सभाकक्ष तथा चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष व वार्ड पार्षद के लिए समाहरणालय के तृतीय तल पर स्थित कमरा नंबर 314 में बैठक आयोजित की

जाएगी। तत्पश्चात उन्हें शपथ दिलाई जाएगी।इसके बाद धनबाद नगर निगम के उप महापौर व चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष के लिए 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रुटनी की जाएगी। दोपहर 1:30 बजे से 1:45 बजे तक नाम वापस लेने का समय निर्धारित है। 2:15 से 3:00 बजे तक धनबाद नगर निगम के उप महापौर व चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष के लिए मतदान किया जाएगा।दोपहर 3:15 से 3:30 बजे तक निर्वाचन परिणाम की घोषणा एवं निर्वाचन प्रमाण पत्र 42 में तामिला के लिए समय निर्धारित है। इसके तुरंत बाद धनबाद नगर निगम के उप महापौर एवं चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष को शपथ ग्रहण कराया जाएगा।

भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के 129 वें स्मरण दिवस पर एडवा सिंदरी नगर कमेटी ने दी श्रद्धांजलि

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : नारी मुक्ति आंदोलन के प्रेरणा स्त्रोत विद्या की देवी भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के 129 वें स्मरण दिवस पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एडवा) सिंदरी नगर कमेटी की ओर से मंगलवार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर रानी मिश्रा ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने देश का पहला बालिकाओं का स्कूल स्थापित किया, यह कार्य उस समय किया जब बालिकाओं के शिक्षा को धर्म और समाज के विरुद्ध माना जाता था।बालिकाओं को शिक्षित करने के कारण उन्हें अनेक प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब वह स्कूल जाती थी तो समाज विरोधी तत्व उनके ऊपर कीचड़ और गोबर फेंक दिया करते थे। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य को पूरा किया। भारत की पहली महिला शिक्षिका को हम नमन करते हैं। कार्यक्रम में सविता देवी, रंजू प्रसाद, रीमा यादव आदि ने अपना वक्तव्य रखा।

झारखंड विधानसभा में धनबाद विधायक राज सिन्हा ने उठाए कई महत्वपूर्ण सवाल

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : झारखंड विधानसभा के सचेतक सह धनबाद विधायक राज सिन्हा ने आज विधानसभा में अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न के माध्यम से धनबाद सहित पूरे झारखंड से जुड़े महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया। विधायक श्री सिन्हा ने राज्य के खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास से जुड़े गंभीर विषय को सदन के समक्ष रखते हुए कहा कि धनबाद जिला सहित झारखंड के विभिन्न जिलों की लगभग 50 प्रतिशत पंचायतें खनन प्रभावित क्षेत्र में स्थित हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 4345 पंचायतों में से लगभग 2000 पंचायतें माइनिंग प्रभावित क्षेत्र में आती हैं, जिनके विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) कोष से प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करने का प्रावधान है। उन्होंने सदन में सवाल उठाया कि डीएमएफटी कोष का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के बजाय रांची, धनबाद, बोकारो, लोहरदगा तथा चतरा जिलों में जिम, डाकबंगला, उपायुक्त कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण में किया गया है, जो कि डीएमएफटी के प्रावधानों के विपरीत है। इस संबंध में महालेखाकार झारखंड के द्वारा भी आपत्ति दर्ज की गई है। विधायक श्री सिन्हा ने सरकार से पूछा कि क्या इस प्रकार के गैरअ नुसूचित क्षेत्रों में किए गए अवैधानिक खर्च की किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने का विचार सरकार के पास है। उन्होंने इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की जोरदार मांग की। इसके साथ ही विधायक श्री सिन्हा ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से झारखंड में संचालित नौ निजी टेक्निकल विश्वविद्यालयों की स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों में अधिकांश स्थानों पर आधारभूत संरचना एवं योग्य फैकल्टी का अभाव है, इसके बावजूद छात्रों को अभियांत्रिकी के विभिन्न विषयों में नामांकन देकर परीक्षाएं कराई जा रही हैं। उन्होंने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से सवाल करते हुए कहा कि क्या यह सही है कि इन निजी टेक्निकल विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की कमी के बावजूद छात्रों के साथ प्लेसमेंट के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे छात्रों एवं अभिभावकों का भयादोहन,आर्थिक शोषण एवं मानसिक शोषण हो रहा है। विधायक श्री सिन्हा ने सदन में कहा कि निजी टेक्निकल विश्वविद्यालयों से अभियंत्रण की पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं को राज्य सरकार अब तक उचित प्लेसमेंट दिलाने में असफल रही है,

रेलवे की कार्रवाई: बुलडोजर ने एक दर्जन घरों को किया ध्वस्त

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : धनबाद के पम्पु तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य में बाधा बन रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मंगलवार को रेलवे ने बड़ा अभियान चलाया। तालाब के समीप रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। जिसमें करीब एक दर्जन से अधिक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।बताया जाता है कि पम्पु तालाब का करोड़ों रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी बीच तालाब के आसपास स्थित रेलवे की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से मकान और खटाल बनाकर कब्जा कर लिया गया था। रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया था, बावजूद इसके कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद रेलवे की ओर से मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से बनाए गए करीब एक दर्जन मकानों और खटालों को तोड़ दिया गया। हालांकि

अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय लोगों की ओर से कुछ विरोध भी देखने को मिला। स्थिति को देखते हुए मौके पर रेलवे अधिकारियों के साथ आरपीएफ और धनबाद थाना की पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया जिसके बाद अभियान जारी रखते हुए इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।इस संबंध में रेलवे अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी इस तरह के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, ताकि पम्पु तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य में कोई बाधा न आए।धनबाद थाना के एसआई देवेन्द्र कुमार ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि पप्पू तालाब स्थित डीएस कॉलोनी में रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ वहां मौजूद रहे। फिलहाल उक्त स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है।

19 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या, रांची से चल रहा था इलाज

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरलीनगर इलाके से मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ 19 वर्षीय युवक अमित कुमार खेत्रोपाल ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।परिजन के अनुसार अमित पिछले कुछ वर्षों से मानसिक तनाव से जूझ रहा था और उसका इलाज रांची में चल रहा था। परिजनों के अनुसार वह करीब पांच वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसका नियमित इलाज कराया जा रहा था।

बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में कोई नहीं था और वह कमरे में अकेला था। इसी दौरान उसने गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो मकान मालिक को शक हुआ। उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद खिड़की से झांककर देखा गया तो युवक फंदे से लटका हुआ दिखाई दिया। तुरंत इसकी सूचना परिजनों और सरायढेला थाना पुलिस को दी गई।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर युवक को फंदे से नीचे उतारा। इसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया।परिजनों ने बताया कि खेत्रोपाल परिवार पिछले 18-19 वर्षों से धनबाद में रह रहा है। युवक के अचानक इस कदम से परिवार के लोग सदमे में हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

इजे एरिया के सेफ्टी प्रबंधकीय टीम ने भौंरा 6 नम्बर गैस रिसाव व गोफ स्थल का किया निरीक्षण

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक टुनेश्वर पासवान के निर्देश पर मंगलवार को इजे एरिया के सेफ्टी प्रबंधकीय टीम ने भौंरा 6 नम्बर गैस रिसाव व गोफ स्थल का निरीक्षण किया।इस दौरान टीम ने कई घरों का भी जायजा लिया। टीम में एरिया सुरक्षा अधिकारी प्रताप कुमार, ए शिंदे, एरिया कार्मिक प्रबंधक सुधांशु महाजन, एरिया मैनेजर प्लानिंग भरत वैष्णव व अन्य अधिकारी शामिल थे।टीम के सदस्यों ने पहले गैस रिसाव स्थल व गोफ को देखा और वहां उपस्थित लोगों से घटना कि पूरी जानकारी प्राप्त किया। मौके पर अधिकारियों ने कहा कि गैस रिसाव व गोफ स्थल के आसपास पुनः मशीन से खोद कर इसमें पानी के साथ बालू को डाल कर अच्छी तरह से बंद किया जायेगा।इस पर मुहल्ले के लोगों ने अधिकारियों को ऐसा नहीं करने की बात कही, लोगो का कहना है कि समीप में ही सैकड़ों घर व मकान है पुनः खुदाई करने से अगर गैस रिसाव व गोफ बढ़ने लगेगी तो फिर मुश्किल हो सकती है। लोगों के नेतृत्व कर रहे नेता श्रवण वर्मा ने टीम के सदस्यों से कहा कि प्रबंधन यहां के लोगों को उचित मुआवजा और आवास देकर जहां रोजगार के साथ पानी बिजली और स्वास्थ्य की सुविधा हो उस स्थान पर सामूहिक रूप से पुनर्वास कराए,हमलोग भी इस असुरक्षित स्थान पर अब रहना नहीं चाहते हैं, यहां कब क्या होगा कुछ पता नहीं है।

घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत बताकर शुरू हो गई कालाबाजारी, उपभोक्ता परेशान

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : ईरान इजराइल एवं अमेरिका के बीच जारी महायुद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थो की हो रही किल्लत को देखते हुए भारत सरकार ने देश की जनता को राहत पहुंचाते हुए यह दावा किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके जमीनी हकीकत कुछ अलग ही नजर आ रही है। ताजा मामला कोयलांचल क्षेत्र का है जहां घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय उपभोक्ताओं का आरोप है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर का निर्धारित मूल्य 970 रुपये है वो कालाबाजारी के जरिए खुलेआम 1200 रुपये तक में बेचा जा रहा है, जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब वे गैस सिलेंडर लेने डिस्ट्रीब्यूटर के कार्यालय पहुंचते हैं तो अक्सर उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि फिलहाल स्टॉक उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी ओर गैस सिलेंडर वितरण करने वाले कुछ हॉकर तथा गैस एजेंसियों में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से उसी सिलेंडर को ऊंची कीमत पर बेचते हुए नजर आते हैं। इन मुनाफाखोरों द्वारा कृत्रिम किल्लत पैदा कर उपभोक्ताओं को मजबूर किया जा रहा है कि वे अधिक कीमत देकर गैस सिलेंडर खरीदें। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि की है, पर ये कालाबाजारी करने वाले लोग प्रति सिलेंडर 200 से 250 रुपये तक अतिरिक्त वसूली कर रहे हैं। इससे खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ रहा है। हाल के महीनों में नागपुर, रुनकता (आगरा), हरिद्वार और रांची जैसे शहरों में पुलिस एवं खाद्य आपूर्ति विभाग की छापेमारी में सैकड़ों सिलेंडर, अवैध रिफिलिंग उपकरण और वाहन जब्त किए गए थे। इन कार्रवाइयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गैस की कालाबाजारी एक संगठित नेटवर्क के जरिए संचालित की जा रही है। कोयलांचल के उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन एवं खाद्य आपूर्ति विभाग से मांग की है कि इस मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही गैस वितरण व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि आम जनता को निर्धारित मूल्य पर आसानी से गैस उपलब्ध हो सके और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

झारखंड विधानसभा में झरिया विधायक रागिनी सिंह ने श्रम व उद्योग से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद : झारखंड विधानसभा में झरिया विधायक रागिनी सिंह ने श्रम एवं उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को जोरदार तरीके से मंगलवार को उठाते हुए सरकार का ध्यान राज्य के श्रमिकों, युवाओं और औद्योगिक विकास की ओर आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य होने के बावजूद यहां के युवाओं को पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। बड़े उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है।

सदन में बोलते हुए विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि राज्य के खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को आज भी सुरक्षा, उचित मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा (ईएसआई, पीएफ) और बेहतर कार्य परिस्थितियों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से धनबाद के झरिया और कोलियरी क्षेत्रों कि समस्याओं का उल्लेख करते हुए

कहा कि भूमिगत आग, भूमि धंसान और प्रदूषण की समस्या से लोग लंबे समय से परेशान हैं, जबकि प्रभावित लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया भी काफी धीमी है।

रागिनी सिंह ने बीसीसीएल क्षेत्र कि समस्याओं को उठाते हुए कहा कि अधिकांश खदानों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोयला उत्पादन कराया जा रहा है।जहां बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं,कंपनी के नियमों के अनुसार कोल श्रमिकों का बी-फॉर्म में नामांकन अनिवार्य है, लेकिन इसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण खदान क्षेत्रों में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें श्रमिकों की जान तक चली जाती है। इसके अलावा क्षेत्र में हजारों असंगठित मजदूरों को नियमानुसार भुगतान नहीं किया जाता और एक ही प्रकार का कार्य करने के बावजूद मजदूरों को अलग-अलग मजदूरी दी जाती है।विधायक ने यह भी बताया कि कई असंगठित मजदूरों के पीएफ की राशि समय पर उनके खातों में नहीं पहुंचती, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12-12 घंटे तक काम कराया जा रहा है, जबकि झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान और अवकाश की व्यवस्था भी पूरी तरह लागू नहीं की जा रही है।सदन में उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने, स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने तथा कौशल विकास और प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

11-03-2026 T.P. Page 4_Layout 1 11-03-2026 07:15 Page 1

संक्षिप्त खबरें

ट्रैक्टर की टक्कर से नानी की मौत, घायल नाती रेफर

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

साहिबगंज : राजमहल के राधानगर थाना क्षेत्र के दक्षिण पियारपुर स्थित आकुनबन्ना नाशघाट के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार नानी-नाती गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दक्षिण पियारपुर निवासी आरिफ शेख (30) अपनी नानी हविलान बीबी (50) को बाइक से किसी काम से उधवा ले जा रहे थे।इसी दौरान सामने से आ रहे मिट्टी लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया।आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए राजमहल अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर सौरभ कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया।परिजनों द्वारा बताया गया कि इलाज के लिए भागलपुर ले जाने के दौरान बोरियो के आसपास हविलन बीबी की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि आरिफ शेख का इलाज के लिए रेफर कर दिया है।घटना की सूचना मिलने पर एएसआई ओमप्रकाश चौहान दल-बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं।स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर अक्सर तेज रफ्तार ट्रैक्टरों के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं।ग्रामीणों ने प्रशासन से ट्रैक्टर चालकों पर सख्ती करने की मांग की है।

रांची सिविल कोर्ट को साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : रांची सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अज्ञात व्यक्ति ने मेल के माध्यम से भेजे गए मैसेज में कहा कि इस बार 14 साइनाइट बम के विस्फोट से कोर्ट उड़ा दिया जाएगा। धमकी देने वाले ने आगे लिखा कि कोर्ट का होने का क्या फायदा जब बेगुनाहों को इंसाफ नहीं मिल पाता।धमकी भरे मैसेज मिलने के बाद रांची पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता कोर्ट परिसर में पहुंचकर तलाशी ले रहे हैं। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक टीम ने कोर्ट के चप्पे-चप्पे की जांच की। सुरक्षा को लेकर कोर्ट परिसर को अस्थायी रूप से पुलिस छावनी में बदल दिया गया है और मुख्य प्रवेश द्वार को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया।यह पहली बार नहीं है जब रांची सिविल कोर्ट को धमकी मिली है। 28 फरवरी को भी अज्ञात शख्स ने मेल भेजकर कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी थी। उस समय भी पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी।पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कोर्ट परिसर की पूरी जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम सतर्क है। आम लोगों और कोर्ट कर्मचारियों को भी आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच, मामले की जांच में भी तेजी लाई गई है और धमकी देने वाले की पहचान के प्रयास जारी हैं।

बजट सत्र:कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर हंगामा, विपक्ष का प्रदर्शन

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दसवें दिन मंगलवार को सदन में उस समय तीखा हंगामा देखने को मिला जब विपक्ष ने राज्य की कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेर लिया।सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए और राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार तथा बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर चर्चा की मांग करने लगे। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के कारण कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही बाधित हो गई।हंगामे के दौरान निर्मल महतो को सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल आउट कराने का निर्देश दिया। हालांकि बाद में सदन में बनी सहमति के बाद उन्हें वापस बुला लिया गया।

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने दुमका में मजदूर यूनियन नेताओं पर गोलीबारी, रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालु के साथ पुलिसकर्मियों की कथित मारपीट और गिरिडीह में महिला दिवस कार्यक्रम के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित बदसलूकी का मुद्दा उठाया।

उन्होंने कहा कि यह अबुआ सरकार नहीं बल्कि बबुआ सरकार बन गई है, जहां अपराधी बेखौफ हैं और अधिकारी बेलगाम। उन्होंने इन मुद्दों पर सदन के अन्य कार्य रोककर विस्तृत चर्चा कराने की मांग की।सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष से कहा कि यदि उनके पास कोई ठोस मामला है तो उसे सदन के पटल पर रखें, सरकार कार्रवाई के लिए तैयार है।बहस के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और विधायक निर्मल महतो के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिससे कुछ समय के लिए सदन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बाद में दोनों पक्षों के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई और कार्यवाही आगे बढ़ी।

बंदूक की नोक पर अपराधियों ने की केनरा बैंक में 15 लाख रुपए लूटे

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

पूर्वी सिंहभूम : बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के साकरा स्थित केनरा बैंक में मंगलवार की दोपहर लगभग 1:45 बजे अज्ञात लुटेरों द्वारा बंदूक(देसी कट्टा)की नोक से लगभग 15 लाख रुपया लेकर फरार हो गया। वही बैंक के सभी स्टाफ एवं ग्राहकों को से मोबाइल फोन तथा सहायक प्रबंधक सौरभ वर्मा से गले का चैन एवं अंगूठी लेकर बंधक बना दिया। उस-ाके बाद बाहर से ताला मार कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बहरागोड़ा पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।कटर से मेन गेट का ताला काट कर सभी को बंधक से मुक्त कराया।लगभग 6 से 7 खाता धारक थे।घटना की सूचना पाकर घाटशिला डीएसपी अजीत कुमार कुजूर पहुंचे।बैंक के अधिकारी से घटना संबंधित विस्तृत जानकारी ली।घटना के बाद पुलिस सघन जांच में जुट गई है।बताया जाता है कि बैंक में 5 से 6 लुटेरे लगभग 1:40 बजे बैंक पहुंचे। कटारी एवं देसी कट्टा दिखाकर बैंक के केस काउंटर में प्रवेश कर लगभग 7 लाख एवं लॉकर के पास

जाकर लगभग 8 लाख रुपया ले लिया। सहायक शाखा प्रबंधक सौरभ वर्मा से सोने की लॉकर खोलने की बात कही।ग्रामीण क्षेत्र के बैंक होने के कारण सोने की लॉकर नहीं रहने की बात बताई। जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद सहायक शाखा प्रबंधक के गले से चैन एवं अंगूठी ले लिया।सभी को बंधक बनाकर फरार हो गया। बैंक के अंदर चार लुटेरे जबकि बैंक के बाहर दो लुटेरे मुंह में माक्स एवं रुमाल से बंधे हुए थे।घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से 5 से 6 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर साकरा (चित्रेश्वर रोड) होते हुए फरार हो गया।लूट के दौरान बैंक के कर्मचारियों के साथ बात हिंदी में कर रहा था जबकि अपने लुटेरों से बांग्ला में भी बात कर रहा थे जबकि घटना से बैंक के कर्मी एवं ग्राहक पूरी तरह से हताश हो गए थे। बंधक से मुक्त के बाद सभी ने राहत की सांस ली।घटना के बाद अपराधियों ने बैंक कर्मी एवं खाता धारकों का मोबाइल फोन साकरा चौक के समीप खेत के अंदर फेंक कर चित्रेश्वर के रास्ते से बंगाल की ओर फरार हो गया।लूट की घटना को अंजाम देने के बाद शाखा प्रबंधक नानाजी राव एक लुटेरे बंदूक लेकर शाखा प्रबंधक के कार्यालय में पहुंचे। शाखा प्रबंधक से कहा कि सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क किधर है। शाखा प्रबंधक ने बहादुरी दिखाते हुए इंटरनेट बॉक्स को दिखा दिया।लुटेरों ने तार काटकर इंटरनेट बॉक्स को अपने साथ ले गए। जबकि हार्ड डिस्क में वीडियो रिकॉर्डिंग हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित है। सीसीटीवी फुटेज चालू होने के बाद घटना का खुलासा हो हो सकता है।इस बैंक में लगभग प्रतिदिन 60 से 100 ग्राहक लेनदेन करने पहुंचते हैं। यह बैंक गांव के अंदर ही है।मगर आज तक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था नहीं की गई है। जिस कारण से लगभग 10 से 15 मिनट तक लुटेरे रुक कर लूट की घटना को अंजाम दिया।बहरागोड़ा में पहली बार दिन के उजाले में लूट की घटना हुई है जो स्थानीय लोगों को सोने के लिए मजबूर कर रहे हैं. ऐसी घटना आज तक कभी नहीं हुई है।बैंक में लूट की घटना को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है।सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों से पूछताछ किया गया। सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चलेगा कि लुटेरों की एक्टिविटी क्या थी। जल्द ही अपराधियों को डिटेक्ट किया जाएगा।

डीआईजी ने सिविल कोर्ट परिसर एवं कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण, दिए महत्वपूर्ण निर्देश

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

पलामू : पलामू क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) किशोर कौशल ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को हमेशा सतर्क और सक्रिय रहना आवश्यक है। किसी भी शिकायत या सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए।आमलोगों की सुरक्षा पुलिस प्रश-ासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीआईजी, पलामू के शहरी क्षेत्र एवं जिले की सुरक्षा तथा विधि-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने पलामू के सिविल कोर्ट परिसर तथा समाहरणालय स्थित सेंट्रल कंट्रोल रूम/सीसीआर रूम) का निरीक्षण किया। उन्होंने आमलोगों से भी विधि व्यवस्था संधारण में पुलिस प्रशासन के साथ सहयोगात्मक भूमिका निभाने की अपील की। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था, अपने कर्तव्य पालन में तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों की सतर्कता तथा उपलब्ध संसाधनों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। डीआईजी के साथ पलामू की पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन भी थीं।डीआईजी ने सिविल कोर्ट परिसर एवं उसके बाहरी संरचना का जायजा लिया।कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का गहन अवलोकन किया। कोर्ट के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बलों की तैनाती, सुरक्षा बलों द्वारा सतर्कता और तत्परता के साथ चेकिंग किये जाने की प्रक्रिया का मुआयना किया। उन्होंने तैनात पुलिस बल को कोर्ट परिसर में आने-जाने वाले लोगों की सतर्कता से जांच सुनिश्चित करने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर विशेष नजर रखने, कोर्ट परिसर में शांति एवं सुरक्षा के लिए सतर्क रहने और सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का सख्त निर्देश दिये।ड-ीआईजी ने पुलिस अधीक्षक के साथ समाहरणालय स्थित सेंट्रल कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपराध निगरानी और सूचना प्रबंधन आदि यहां संचालित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस कर्मियों की सतर्कता, उपलब्ध संचार प्रणाली, आपातकालीन सूचना प्रबंधन, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम में प्राप्त लाइव फूटेज की स्थिति, उसकी गुणवत्ता, विभिन्न थानों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन, फाइलों का रखरखाव और त्वरित कार्रवाई की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने यहां नियुक्त/प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करने तथा सभी थानों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने शहर की सुरक्षा के लिए लगाये गये सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्राप्त लाइव फूटेज की लगातार मॉनिटरिंग करने, अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने, रिकॉर्ड्स अद्यतन करते हुए उसका सही से रखरखाव, फाइलों का शीघ्र निष्पादन और पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतते हुए आमजनों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान ना दे, संदिग्ध सूचना मिलते ही पुलिस को दें जानकारी

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिले में सोशल मीडिया पर बच्चों की चोरी, गुमशुदगी और अपहरण से जुड़ी अफवाहों के तेजी से फैलने के बीच खरसावां पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खरसावां थाना प्रभारी गौरव कुमार ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली किसी भी सूचना पर बिना सत्यता की जांच किए विश्वास न करें। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बच्चा चोरी से संबंधित कई तरह की खबरें और संदेश तेजी से प्रसारित किए जा रहे हैं।इससे लोगों के बीच भय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है. पुलिस जांच में ऐसे अधिकांश मामलों को अफवाह पाया गया है।खरसावां थाना प्रभारी गौरव कुमार ने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाना कानूनन अपराध है।वहीं इन अफवाहों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट, प्रताड़ना या भीड़ द्वारा हिंसा करना भी गंभीर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि इस तरह की कोई संदिग्ध सूचना या घटना सामने आती है तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें या आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क करें।साथ ही खरसावां थाना को भी सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अफवाहों से बचना और सही जानकारी साझा करना सभी की जिम्मेदारी है।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में तीनदिवसीय एग्रोटेक किसान मेला 14 मार्च से, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांचीः क बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपने कांके प्रांगण में 14 से 16 मार्च तक आयोजित किये जानेवाले राज्यस्तरीय एग्रोटेक किसान मेला का उद्घाटन 14 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे।राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 16 मार्च को समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मेला का केन्द्रीय विषय वस्तु ह्यटिकाऊ कृषि हेतु जलवायु अनुकूल तकनीकी नवाचारह्न है क विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीख तथा विधायक राजेश कच्छप, अमित कुमार एवं सु-रेश कुमार बैठा की उपस्थिति रहेगीक मेला के दूसरे दिन पशु-पक्षी प्रदर्शनी का उदघाटन विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो करेंगे जबकि राज्यसभा सदस्य डॉ महुआ माजी महिला कृषक गोष्ठी का उद्घाटन करेंगी

कराष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा महिला गोष्ठी में विशिष्ट अतिथि रहेंगी।

बीएयू के कुलपति डॉ सुनील चन्द्र दुबे ने बताया कि मेला में लगभग 135 स्टाल लगाये जा रहे हैं जहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, संकायों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के अलावा झारखण्ड में कार्यरत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध संस्थान, कृषि से संबंधित विभाग, बीज, कृषि यंत्र एवं उर्वरकों के निमार्ता एवं बिक्रेता, बैंक एवं वित्तीय संस्थान तथा स्वयंसेवी संगठन अपनी तकनीक, सेवाएँ एवं उत्पाद प्रदर्शित करेंगे कबिक्री हेतु विसिध कृषि इनपुट भी उपलब्ध रहेंगे कइस अवसर पर आनेवाले किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा खेती-बारी सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक तकनीकी परामर्श भी प्रदान किया जायेगा कनिदेशक प्रसार शिक्षा डॉ रेखा सिन्हा के निर्देशन में विभिन्न समितियां युद्ध स्तर पर मेला की तैयारी में लगी हैं कमेला का उद्देश्य किसानों, कृषक महिलाओं एवं युवा उद्यमियों को उन्नत कृषि, पशुपालन, वानिकी, डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि यंत्रीकरण, खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन तथा घरेलू एवं अन्य कुटीर उद्योगों से संबंधित आधुनिक तकनीकों की जानकारी देना हैकइस अवसर पर फल, फूल, सब्जी, मसालों, सजावटी, औषधीय एवं सगंधीय पौधों से संबंधित उद्यान प्रदर्शनी, पशु-पक्षी प्रदर्शनी, कृषि यंत्र प्रदर्शनी, किसान गोष्ठी, प्रायोगिक प्रक्षेत्रों का परिभ्रमण, महिला कृषक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है।

पलामू में धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने का निर्देश,20 दिनों में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

पलामू : जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू की अध्यक्षता में मंगलवार को धान अधिप्राप्ति योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।बैठक में जिले के सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों के संचालक,राइस मिलर तथा नोडल पदाधिकारी-सह-दंडाधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पलामू जिले में 2 लाख 50 हजार क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरुद्ध अब तक 1 लाख 63 हजार क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है जबकि करीब 87 हजार क्विंटल धान की खरीद अभी शेष है।जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू ने सभी केंद्र संचालकों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में शत-प्रतिशत पूरा करना सुनिश्चित करें और किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य से कम धान की खरीदी न हो।धान खरीद के लिए अभी लगभग 20 दिन

शेष है,जिसमें शेष लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सकता है।बैठक में यह भी बताया गया कि पूर्व में राइस मिलरों के चयन एवं धान उठाव में कुछ कठिनाइयां आ रही थी,लेकिन अब राइस मिलरों द्वारा धान का उठाव कार्य तेज कर दिया गया है। अब तक करीब 60 हजार क्विंटल धान का उठाव भी किया जा चुका है तथा शेष धान का उठाव भी तेजी से करने का निर्देश सभी राइस मिलरों को दिया गया है।जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि इस बार किसानों को एकमुश्त राशि भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।भुगतान को लेकर अब तक किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।विभाग एवं निगम मुख्यालय,रांची स्तर से भी इस-ाकी लगातार समीक्षा की जा रही है और राशि उपलब्ध होते ही किसानों के खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है साथ ही सभी प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी-सह-दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे समय-समय पर क्रय केंद्रों का निरीक्षण करते रहें,ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और क्रय केंद्रों पर किसी भी तरह की अनियमितता न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऑनलाइन ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज धान खरीद की मात्रा के अनुरूप ही धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर भंडारित है।

पीवीयूएनएल में सीआईएसएफ का 57वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रामगढ़ : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) यूनिट पीवीयूएनएल पतरातू के इकाई परेड ग्राउंड में मंगलवार को 57वां स्थापना दिवस उत्साह व गरिमा के साथ मनाया गया।कार्यक्रम का आयोजन कमांडेंट विभु सिंह प्रतिहार, उप कमांडेंट संजीव कुमार सद्दी तथा सहायक कमांडेंट गोरधन जाट की उपस्थिति में किया गया।इस अवसर पर सीआईएसएफ के अधिकारी, जवानों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे।कार्यक्रम के दौरान सीआईएसएफ के तीन प्लाटून द्वारा परेड का प्रदर्शन किया गया. अनु-शासित और आकर्षक परेड को देखकर उपस्थित दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ जवानों का उत्साहवर्धन किया।इसके अलावा सीआ-ईएसएफ कर्मियों के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया गया।इस अवसर पर कमांडेंट विभु सिंह प्रतिहार ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देश की औद्योगिक इकाइयों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते आ रहे हैं।स्थापना दिवस जवानों को अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी।

पीएमएवाई अवास कमीर्यों ने जिला मुख्यालय में दिया धरना,कहा सरकार मांगे पुरी करें अन्यथा सात अप्रैल से अनिश्चीत कालीन हड़ताल

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

सरायकेला : झारखंड राज्य आवास कर्मी संघ, रांची के आह्वान पर सरायकेला खरसावां जिला ईकाई द्वारा अपने मांगों को लेकर मंगलवार को जिला समाहरणालय के बहार धरना प्रदर्शन किया।धरना प्रदर्शन में सरकार से मांगों को पुरा करने अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दिया। अवास कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष सावन सोय ने कहा कि मांगों को लेकर 16 फरवरी से 18 फरवरी तक

काला बिल्ला लगा कर काम कर चुके हैं, बावजुद हमारी मांगों को लेकर सका-रात्मक पहल नही किया गया साथ ही 23 फरवरी से 25 फरवरी तक कलमबंद हड़ताल भी किया गया था। उन्होंने कहा कि मांगें पुरा नही होने की स्थिति में 17 मार्च से 20 मार्च तक अवास कर्मी हडताल में रहेंगे इसके पश्चात आगामी सात अप्रैल से अनिश्चीतकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मौके पर पीएमयू कर्मी जिला समन्वयक सत्यवान कुमार, प्रशिक्षण समन्वयक बसंत कुमार साहू, प्रखंड समन्वयक सावन सोय,श्यामसुंदर महतो, ठाकुर सोरेन,लिपिक रावत,बीना बंकीरा,राकेश कुमार महतो,कीर्ति महतो, प्रखंड ऑपरेटर शिवा बेहरा,शिबू मुर्मु,ज्योति कुमारी,लक्ष्मी महतो, गीता, भीष्म मुंडा, संतोष जारिका, अभिषेक रावत सहित अन्य उपस्थित थे।जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मियों के पदों की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग समिति से किया जाए।जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मियों का मासिक मानदेय को बदलकर ग्रेड-पे का निर्धारण किया जाए। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं कर्मियों को योजना कार्य के नियमित अनुश्रवन एवं क्षेत्र भ्रमण के लिए देय मासिक मानदेय का 5% क्षेत्र भ्रमण भत्ता दिया जाए।सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को अकारण योजना कार्य से विमुक्त हटाने की परिस्थिति में विभाग स्तर से अपील करने का अवसर प्रदान की जाय, इस के लिए विभागीय स्तर पर अपीलीय समिति का गठन किया जाए।सभी पदाधिकारियों कर्मियों का सेव-ाकाल लगभग 8 वर्ष से अधिक हो गया है इस लिए प्रतिवर्ष नवीनिकरण की बाध्यता को समाप्त करते हुए सेवा विस्तार साठ वर्ष किया जाए।

संक्षिप्त खबरें

संघर्षों से भरी रही सावित्रीबाई फुले की जिंदगी, बालिका के शिक्षा के लिए किया ऐतिहासिक काम

फतेहपुर (गया जी)(एजेंसी) : फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित प्लस टू सीपीएस स्कूल, प्लस टू प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल, प्लस टू राम सहाय हाई स्कूल और गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में मंगलवार को भारत की पहली महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की 128वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शिक्षकों व विद्यार्थियों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष, साहस और सामाजिक बदलाव का प्रतीक रहा है। उन्होंने उस दौर में बालिकाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई, जब समाज में महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था। समाज में व्याप्त लिंगभेद, बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ उन्होंने साहसिक संघर्ष किया। वक्ताओं ने कहा कि सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों के बीच शिक्षा का अलख जगाया और समाज में समानता की भावना को मजबूत किया। इसी कारण उन्हें भारतीय नारीवाद की जननी भी कहा जाता है। सभा में वक्ताओं ने सरकार से मांग की कि सावित्रीबाई फुले के जीवन और योगदान को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए तथा उनके नाम पर जनहितकारी योजनाएं संचालित की जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों से प्रेरणा ले सकें।

कार्यक्रम में निदेशक राकेश कुमार टुन्नी, प्रबंध निदेशक राजकुमार कुन्नी, प्राचार्य उमेश कुमार, प्राचार्य सीतांशु कुमार, मोटीवेटर डी कुमार, प्राचार्य डी कांति सहित विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित है।

रेलकर्मियों ने महाप्रबंधक से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से कराया अवगत

हाजीपुर(एजेंसी) : आज मुख्यालय, हाजीपुर में 05 रेलकर्मियों ने पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह से मुलाकात की तथा अपनी

समस्याओं से उन्हें अवगत कराया । महाप्रबंधक ने संबंधित विभागों को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में केस निष्पादन के निर्देश दिए।विदित हो कि रेलकर्मियों की विभागीय समस्याओं के निष्पादन के उद्देश्य से महाप्रबंधक से मुलाकात हेतु प्रत्येक मंगलवार का दिन निर्धारित किया गया है। इसके लिए रेलकर्मी अपना नाम पूर्व में कार्मिक विभाग में पंजीकृत करवाकर मंगलवार को महाप्रबंधक से मुलाकात कर अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकते हैं ।

वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट विकास के लिए टेंडर जारी, 38.64 करोड़ से होगा निर्माण:सम्राट चौधरी

पटना, (एजेंसी) : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट के विकास और उन्नयन यानि अपग्रेडेशन के लिए ईपीसी मोड पर ई-टेंडर जारी किया है।

यह टेंडर मौजूदा एयरपोर्ट को कोड-2बी श्रेणी के विमानों के संचालन के अनुरूप विकसित करने के लिए जारी किया गया है।

परियोजना की अनुमानित लागत 38.64 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। निर्माण कार्य की अवधि 11 महीने तय की गई है।

एएआई द्वारा जारी टेंडर के अनुसार परियोजना के तहत प्री-फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर टर्मिनल भवन, प्री-इंजीनियर्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) टावर, प्री-इंजीनियर्ड फायर स्टेशन तथा अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत बनाना है।

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य में हवाई संपर्क और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी हाल में ही मुजफ्फरपुर में निमार्णाधीन हवाईअड्डे के रनवे के निर्माण के लिए भी 43 करोड़ 13 लाख रुपये की टेंडर जारी किया गया है। और अब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वाल्मिकी नगर एयरपोर्ट के विकास और उन्नयन के लिए टेंडर जारी किया गया है। उन्होंने कहा-वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट के विकास से बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज समेत उत्तर बिहार और सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम है। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

समृद्धि यात्रा : सीएम के सुपौल दौरे पर डीएम-एसपी की संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग

सुपौल, (एजेंसी) : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत सुपौल दौरे को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग कर मीडिया को विस्तृत जानकारी दी।

जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्मली प्रखंड स्थित निर्मली रिंग बांध की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य का उद्घाटन किया। यह कार्य वर्ष 2025 की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित किया गया था, जो अब पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर बांध का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा निर्मली अनुमंडल कार्यालय के सामने मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए सरकारी योजनाओं के स्टॉलों का अवलोकन किया और कई योजनाओं के लाभुकों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया।

निर्मली में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि छातापुर और त्रिवेणीगंज में सुरसर नदी चैनलाइजेशन और तटबंध मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है। वीरपुर में निबंधन कार्यालय के नए भवन के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। सुपौल स्टेडियम के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है, जबकि बाबा तिल्हेश्वर नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा त्रिवेणीगंज और पिपरा बाजार के बाईपास निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। नए बस स्टैंड और हवाई अड्डा परियोजना पर भी काम चल रहा है।

बिहार में सुधा बूथों के माध्यम से होगी बकरी के दूध की बिक्री

पटना, (एजेंसी) : बिहार में बकरीपालन को बढ़ावा देने और इससे जुड़े उत्पादों के बाजार को विस्तार देने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब समूचे बिहार में सुधा बूथों के माध्यम से बकरी के दूध की बिक्री की जाएगी, जबकि बकरे के मांस की बिक्री नगर निगम और नगर निकायों के जरिए करायी जाएगी। इसके लिए डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही राज्य कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। इस बात की जानकारी विभाग के सचिव शीर्षत कपित अशोक ने दी। वह पटना के एक स्थानीय होटल में जलवायु अनुकूल बकरीपालन एवं प्रबंधन विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का उद्घाटन डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता और विभाग के सचिव ने संयुक्त रूप से किया। सचिव शीर्षत कपित अशोक ने कहा कि सरकार की योजना है कि जल्द ही राज्य की सभी पंचायतों में सुधा बूथ स्थापित किए जाएं, जिससे डेयरी और पशुपालन से जुड़े उत्पादों की बिक्री को मजबूत बाजार मिल सके।

पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस वितरण को लेकर उठाए सख्त कदम

पटना, (एजेंसी) : मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के कारण वैश्विक स्तर पर एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने से पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस वितरण को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। ताजा निर्देशों के मुताबिक 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सामान्य आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के कोटे में भी करीब 20 से 25 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्देश दिया गया है। सोमवार आधी रात से लागू हुए नए सरकारी निर्देशों के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडरों की डिलीवरी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की

सप्लाई पर भी सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। इस फैसले का असर अब सीधे आम लोगों और खासकर शादी-विवाह वाले घरों पर पड़ रहा है, जहां बड़े पैमाने पर खाना बनाने की तैयारी रहती है। बताया जा रहा है कि इन नए नियमों के लागू होने के बाद कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। लोग असमंजस में हैं कि उन्हें समय पर गैस सिलेंडर मिल पाएगा या नहीं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और कैटरिंग से जुड़े कारोबारियों के बीच भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी बंद होने से होटल, रेस्टोरेंट और शादी-विवाह जैसे बड़े आयोजनों में गैस की किल्लत होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी अब गैस सिलेंडर लेना पहले की तुलना में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पेट्रोलियम कंपनियों ने एक वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडर के नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। जिन उपभोक्ताओं ने चालू वित्तीय वर्ष में पहले ही 12 सिलेंडर ले लिए हैं, उनकी नई बुकिंग पर सिस्टम ने स्वतः रोक लगा दी है।

प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या

बेगूसराय, (एजेंसी) : बिहार के बेगूसराय के सिंघौल थाना इलाके के नागदह इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने 52 साल के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जिले के डंडारी थाना इलाके के मेहा गांव के रहने वाले वरुण सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने उनपर तब हमला किया जब वह कुछ और लोगों के साथ किसी व्यावसायिक काम से जा रहे थे। वरुण को कई गोलियां लगीं और वह मौके पर ही गिर पड़े। आस-पास के लोग उन्हें बेगूसराय सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेगूसराय के एसपी मनीष ने कहा, हम हत्या में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हत्या का मकसद साफ हो जाएगा।

मेगा टिकट जांच में पकड़े गए 380 बेटिकट यात्रियों से 2.10 लाख वसूला गया जुर्माना

गया जंक्शन पर बेटिकट यात्रियों के खिलाफ चलाया गया मेगा टिकट जांच अभियान

गया जीः पूर्व मध्य रेलवे के डीडीयू रेल मंडल अंतर्गत गया जंक्शन पर ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने के लिए मेगा टिकट जांच अभियान चलाया गया। डीडीयू रेल मंडल व गया जंक्शन की संयुक्त आधिकारिक टीम के नेतृत्व में टीटीई, टीसी व कॉमर्शियल विभाग द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान 380 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा गया। पकड़े गए पर टिकट यात्रियों

से जुमार्ने के रूप में 2 लाख 10 हजार रुपए की राजस्व वसूली की गई। डिड यू रेल मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक अरविंद कुमार और गया जंक्शन के मुख्य टिकट निरीक्षक(प्रशासन) आरआर सिन्हा के नेतृत्व में टीटीई,टीसी और कमर्शियल विभाग की टीम प्लेटफार्म, फुट ओवरब्रिज और विभिन्न ट्रेनों में सघन जांच की।

अभियान के दौरान टिकट जांच दल ने यात्रियों के टिकटों की बारीकी से जांच की और बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती। कई यात्रियों से मौके पर ही जुमार्ना वसूला गया। डिड यू रेल मंडल के वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक राजीव रंजन ने बताया कि डीआरएम उदय सिंह मीना के दिशा निर्देश में संचालित टिकट जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य रेलवे को राजस्व नुकसान से बचाना और यात्रियों को नियमों के प्रति जागरूक करना है। जांच के दौरान टीम ने यात्रियों को वैध टिकट लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी। साथ ही बिना टिकट यात्रा करने पर लगने वाले जुमार्ने और कानूनी कार्रवाई की जानकारी भी दी गई। उन्होंने बताया कि आगे भी समय-समय पर ऐसे विशेष अभियान चलाए जाएंगे ताकि रेल यात्रा को व्यवस्थित और नियमों के अनुरूप बनाया जा सके।

मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के 5 जिलों को शामिल करने वाली दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को दी स्वीकृति

इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 192 किलोमीटर की होगी वृद्धि

इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 4,474 करोड़ रुपये है और ये वर्ष 2030-31 तक पूरी हो जाएंगी

नई दिल्ली/हाजीपुर(एजेंसी) : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज रेल मंत्रालय की लगभग 4,474 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली दो परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं सैंथिया-पाकुड़ चौथी लाइन और संतरागाछी-खड़गपुर चौथी लाइन बढ़ी हुई रेल लाइन क्षमता से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। ये मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने में सहायता मिलेगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिसमें एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध आवागमन के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों के 5 जिलों को शामिल करने वाली 2 परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 192 किलोमीटर तक बढ़ाएंगी।स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना लगभग 5,652 गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिनकी आबादी लगभग 147 लाख है।प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों, जैसे बोलपुर-शांतिनिकेतन, नंदिकेश्वरी मंदिर (शक्तिपीठ), तारापीठ (शक्तिपीठ), पटाचित्र ग्राम, धडिका वन, भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य, रामेश्वर कुंड आदि के लिए रेल संपर्क में सुधार होगा।स्वीकृत परियोजनाएं कोयला, पत्थर, डोलोमाइट, सीमेंट, स्लैग, जिप्सम, लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, पीओएल, कंटेनर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 31 मिलियन टन माल ढुलाई की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी। रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा दक्ष परिवहन माध्यम होने के नाते, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने में सहायता करेगा, तेल आयात (6 करोड़ लीटर) को कम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (28 करोड़ किलोग्राम) को कम करेगा, जो 1 करोड़ पौधारोपण के बराबर है।

दरभंगा में आरओबी एवं एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में आएगी तेजी : संजय सरावगी

पटना, (एजेंसी) : दरभंगा शहर की सड़क जाम को दूर करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर और निमार्णाधीन आरओबी के निर्माण कार्य में अब तेजी आएगी। शहर के तीनों ऐतिहासिक तालाब हराही, दिग्घी और गंगासागर के एकीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी अब बिहार पुल निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। इन तीनों तालाबों के एकीकरण का कार्य शीघ्र आरंभ होगा।यह जानकारी बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने दी।

पटना में उद्योग सह पथ निर्माण विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई, जिसमें पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव पंकज पाल सहित पुल निर्माण विभाग के वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि बैठक में 1868 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत दरभंगा रेलवे स्टेशन से आमसझदरभंगा एक्सप्रेस-वे तक (भाया दोनार चौक, कपूर्री चौक) तथा कपूर्री चौक से एकमी चौक तक (भाया लहेरियासराय टावर, लोहिया चौक) मार्ग के अपग्रेडेशन एवं एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण को लेकर विशेष चर्चा की गई।उन्होंने बताया कि बैठक में एलिवेटेड कॉरिडोर लोहिया चौक होते हुए पंडासराय में बन रहे आरओबी से भी जुड़ेगा, जिसके लिए सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की प्रगति जमीनी स्तर पर आमजन को दिखाई देने लगेगी। इस परियोजना के पूर्ण होने से शहर में यातायात की बड़ी समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी तथा लोगों को सुगम आवागमन के साथ तेज कनेक्टिविटी की सुविधा प्राप्त होगी।सरावगी ने बताया कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने तथा निर्माण की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता न करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री के दौरे की आहट से मायापुर में बढ़ी हलचल, तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर व हेलिपैड व सभा स्थल का किया निरीक्षण

साफ-सफाई, सड़क दुरुस्ती व सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

फतेहपुर (गया जी)(एजेंसी) : समृद्धि यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन की आहट से मायापुर में प्रशासनिक सरगर्मी बढ़ गई है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मंगलवार को जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने अधिकारियों के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर का निरीक्षण कर हेलिपैड से लेकर सभा स्थल तक की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी कार्य समय से पहले पूरा करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।

डीएम ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर, हेलिपैड व सभा स्थल का निरीक्षण किया।

डीएम शंशाक शुभंकर ने निरीक्षण के दौरान सभा स्थल, ग्रीन कक्ष, स्टॉल स्थल, हेलिपैड तथा पार्किंग स्थल सहित पूरे परिसर का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी तैयारियां तय समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएं। उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर को आकर्षक बनाने के लिए कार्यालय भवन के सामने स्थित गार्डन में दो दिनों के अंदर घास और फूल-पौधे लगाने के साथ ही परिसर की दीवारों की रंगाई-पुताई कराने का निर्देश दिया है। साथ ही हेलिपैड से सभा स्थल, मिलेट्स फसल क्षेत्र और स्टॉल स्थल तक जाने वाली सड़क को दुरुस्त करने, लटकते बिजली तारों को ठीक कराने और पूरे परिसर में साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा।

डीएम ने पूरे परिसर का पैदल भ्रमण कर एक-एक व्यवस्था का बारीकी से किया अवलोकन

डीएम ने क्षेत्र की सड़कों व पगडंडियों के समतलीकरण तथा निमार्णाधीन नाली-गली कार्य को तेजी से पूरा कराने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त पैन और तालाब में पानी भरने, आहर-पैन की ड्रेसिंग कराने तथा पुलिया की पेंटिंग सहित अन्य जरूरी कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने पूरे परिसर का पैदल भ्रमण करते हुए एक-एक व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

56 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मायापुर

मायापुर स्थित मिलेट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीएम शशांक शुभंकर को अवगत कराते हुए जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मायापुर 56 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चतुर्थ कृषि रोडमैप 2023झ 28 के तहत फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस सेंटर की स्थापना अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से की जा रही है। प्रशासनिक-सह-प्रशिक्षण भवन का निर्माण अंतिम चरण में है, जहां वैज्ञानिकों के कक्ष, किसानों के आवास, प्रशिक्षण हॉल व कैंटीन की व्यवस्था की गई है। संस्थान में रिसर्च लैब और जर्म प्लाज्म स्टोरेज भी तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 40 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में खेती की जा रही है। प्रक्षेत्र पर दो तालाब व एक आहर अवस्थित है। एक थ्रेडिंग फ्लोर तथा एक कम्पोस्टिंग इकाई और तीन हजार मीटर का चहारदीवारी का निर्माण कराया गया है। प्रक्षेत्र को पांच ब्लॉकों में बांटकर फील्ड डेमोंस्ट्रेशन, शोध व बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। यहां आधुनिक कृषि मशीनों की भी व्यवस्था है।

संपादकीय

भारत में रसोई गैस का संकट देशभर में अफरा-तफरी

ईरान-इजरायल युद्ध का असर अब भारत में बड़े पैमाने पर दिखने लगा है। रसोई गैस की आपूर्ति पर जिस तरह के प्रतिबंध पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे हैं, उसके बाद स्थिति बुरी तरह से गड़बड़ा गई है। होटल और रेस्टोरेंट के संचालकों को कामर्शियल गैस के सिलेंडर की आपूर्ति बंद कर दी गई है। जिसके कारण देशभर के हजारों रेस्टोरेंट और होटल बंद होने की कगार पर हैं। वहीं शादी-विवाह का सीजन होने के कारण इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। गैस सिलेंडर की कीमत पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा बढ़ा दी गई है। गैस की डिलीवरी भी मनमाने तरीके से की जा रही है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने आनन-फानन में एस्मा लागू किया है। इससे स्पष्ट है, भारत में रसोई गैस को लेकर अचानक पैदा हुए संकट ने आम जनता से लेकर छोटे कारोबारियों को मुसीबत में डाल दिया है। कामर्शियल एवं घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर लगी पाबंदियों और आपूर्ति में आई रुकावटों के कारण देश के कई शहरों में होटल, रेस्टोरेंट और छोटे खाद्य व्यवसाय बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। देश भर के कई स्थानों के होटल और ढाबों ने अस्थायी रूप से अपने व्यवसाय को बंद करने की घोषणा कर दी है, जिससे लाखों लोगों का रोजगार और करोड़ों लोगों की नौकरी में संकट उत्पन्न हो गया है। लोगों को चाय पानी नाश्ता और खाना भी कारोबारी स्थलों पर नहीं मिल पा रहा है। कामर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल देश के लाखों छोटे बड़े व्यवसायों में होता है। जहां करोड़ों लोग काम करते हैं। सड़क किनारे चाय, पोहा, वड़ा-पाव, कुलचे-भटूरे बेचने वाले छोटे दुकानदार से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक सभी एलपीजी गैस पर निर्भर हैं। गैस सिलेंडर की सप्लाई में रुकावट आती है, बुकिंग पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसका सीधा असर करोड़ों लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पडने जा रहा है। देश के कई शहरों में एजेंसियों के बाहर सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। कहीं-कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति भी गड़बड़ाने लगी है। हर तरफ बेचैनी का माहौल देखने को मिल रहा है।

फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करनेवाला मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त करता है।
: गीता

धर्म करते हुए मर जाना अच्छा है पर पाप करते हुए विजय प्राप्त करना अच्छा नहीं।
: महाभारत

कहो तो कह दूं- जीजा अस्थाई व्यवस्था, फूफा होना ही जीवन का स्थाई भाव

फूफा हो जाना तो विधि का विधान है ! सड़क किनारे ,फुटपाथ पर घटी दरों पर बिकती ,पुरानी धुरानी ,सैकेंड हैंड किताबें देखी है ना आपने , कुछ बुजुर्ग , अधेड़ औरते ,आदमी कभी कभी ठिठक कर रूक जाते हैं उसके सामने कुछ ढेर को टटोलते हैं , काम की चीज निकालने की कोशिश करते है ,जो चीज कभी हजार की थी वो सौ पचास की हैसियत पा लेती है आमतौर पर ये ढेर ,बेशकीमती ज्ञान का भंडार जवान छोरे छोरियों द्वारा अनदेखा ही किया जाता है ! फूफा होना ऐसा ही ढेर हो जाना है ।

फूफा दरअसल ओल्ड एडीशन है जीजा का ।जीजा जब पुराना पड़ जाता है तो फूफा हो जाता है ! फूफा वह कच्चा आम बना रह जाना चाहता है जिसे देख कभी उसकी सालियों के मुँह मे पानी भर आया करता था ,पर वो वक्त के हाथो पकता है ,और अचार डालने जैसा भी नही बचता !

जीजा हारता है वक्त से ,उसका बस चले तो वो घड़ी की सुइयों से लटक कर रोक ले उसे ,पर इतिहास गवाह है कोई जीजा आज तक कर नही पाया है ऐसा ।अपनी खुद की कमर पर ही बस नही चलता उसका । वो लाख कोशिश करता है वो चौतीस से अडतीस के खतरे के निशान पर जा पहुँचती है, उसका अपना पेट उसे अपने घुटने देखने से रोक देता है ,सर की लहलहाती फसल उजड़ चुकी होती है अब बिना चश्मे के सालियों को पहचानना कठिन हो चलता है और ससुराल की सीढियाँ चढने मे घुटने भी अनमने होने लगते हैं।

वैसे भी फूफा हो जाना तन से ज्यादा मन का दुख है ,मन अटका होता है जीजा होने मे और तन फूफा हो चुका होता है ! ऐसे मे यदि बंदे के पास धन हो तब थोडी सी और मोहलत मिल जाती है। धन उसे फूफा की अधोगति मे पड़ने के पहले जीजा की योनि मे बने रहने के लिये कुछ और फालतू साल दिला देने मे मदद करता है

ससुराल ऐसी जगह होती है जहाँ जाना ही होता है आदमी को। ये वो जगह है जहाँ जीजा रहते आदमी उछल उछल कर जाता है जाने के बहाने तलाश करता है, पर फूफा होते ही ये सब बदल जाता है बचता है वो ससुराल जाने से । फूफा होने के बाद ससुराल जाना ,रिटायरमेंट के बाद उस ऑफिस की सीढियाँ चढने जैसा है जहाँ कभी आप बॉस रह चुके हों ।

फूफा हो चुके आदमी को ससुराल मे होते हुये गौर से देखियेगा अगली बार फूफा होने के बाद ससुराल मे बंदा लालकिले मे कैद शाहजहाँ टाईप की चीज हो जाता है ताजमहल उसकी पहुँच से दूर होता है अब वो अपने सिंहासन पर किसी ताजा ताजा जवान हुये लड़के को देख बैचैन होता है , सोफे पर करवटें बदलता है , किसी बात की शिकायत आमतौर पर करता नही ! करता है तो आवाज मे दम नही होती।

फूफा हो जाना सूरज से प्लूटो हो जाना है ! वो ससुराल के सौरमंडल मे होता तो जरूर है पर उसे गिना नही जाता ,वो ससुरालियों की कुंडली मे होता तो है पर किसी का कुछ बना बिगाड़ नही पाता सो अनदेखा होता है वो इस अनदेखी पर भुनभुनाता तो है पर उसे मन ही मन करना होता है ऐसा ।

ये सब लिखा क्यो हैं मैनें ? वास्तव में ये तो सलाह है उन्हें जो फिलहाल जीजा हैं जीजा हैं तो ज्यादा फुदकिये मत, जीजा होना तो अस्थायी व्यवस्था है ,फूफा होना ही जीवन का स्थायी भाव है ! अपने आपको फूफा होने के लिये अभी से तैयार करें इसी मे सार है और यदि फूफा हो ही चुके हैं आप तो धीरज बनाये रखें, हौसला रखें, समझायें खुद को , ये तो होना ही था एक ना एक दिन। ,चुप रहने की आदत डाल लें और जब किसी सभा समारोह मे बतौर मार्गदर्शक मंडल तीसरी लाईन मे खिसका दिये जायें तो बुरा ना मानें ! समय किसी का सगा नही होता ! फूफा का तो हरगिज नही !

ऊपर नीचे होते सोना चांदी

अब आदमी किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें, हाल तो ये है कि अपने लोगों पर भी भरोसा उठ चुका है। नेताओं पर उनके कर्मों के कारण लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया है, क्योंकि वे कहते कुछ है और करते कुछ और हैं पॉलीटिकल पार्टी पर भी भरोसा बचा नहीं है और अब तो सोना चांदी पर भी भरोसा करना बड़ा कठिन हो गया है ।एक जमाना था जब लोग बाग कहते थे कि सोना खरीद लो संकट के वक्त काम आएगा ,चांदी खरीद लो जब कभी बुरा वक्त आएगा तो चांदी बेचकर अपना गुजारा कर लेना लेकिन लगता है कि दुनिया जिस ढंग से चल रही है उसी ढंग से सोना और चांदी भी उसी रंग में रंग गए हैं, कब गिर जाए कब ऊपर उड़ जाए कोई नहीं जानता यहां तक कि जो अपने आप को शेयर मार्केट का या सोने चांदी के उस्ताद मानते हैं वे भी नहीं जानते कि कब सोने का भाव ऊपर हो जाएगा और चांदी जमीन पर आ जाएगी । कुछ दिन पहले चांदी ने ऐसी छलांग लगाई जिसको देखकर बंदरों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली कि इतनी बड़ी बड़ी छलांग तो वे भी नहीं लगा सकते। देखते-देखते चार लाख के पास पहुंच गई चांदी। भाव बढ़ रहे थे तो लोगों ने धकापेल चांदी की खरीद शुरू कर दी और फिर एक हफ्ते में चांदी ने उनकी लुटिया डुबो दी और एक ही झटके में दो लाख पर वापस आ गई, अब जिन लोगों ने ज्यादा दामों में चांदी खरीदी थी वे चांदी पर सर रखकर रो रहे हैं जार जार आंसू बहा रहे हैं कि अब क्या पता कब ये चांदी चार लाख जाएगी, यही हाल सोने का है फिर भी सोने पर थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता है अपना तो लोगों से यही कहना है कि भैया जब इंसान का इंसान पर से भरोसा उठ गया है तो फिर सोना चांदी पर भरोसा काहे को करते हो, लेकिन कहते हैं ना लालच बुरी बला सब कुछ देखने के बाद भी लोग बाग सोना चांदी खरीदने में लगे है जब नुकसान होता है तो सोना चांदी को गाली देते हैं और जब फायदा होता है तो अपनी बुद्धिमत्ता को।

खैरात ही तो है वोट बैंक

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शोध रिपोर्ट में यह कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा फ्रीबीज जैसी योजनाएं जो खैरात के रूप में दी जा रही है उससे देश का विकास रुक रहा है इसकी वजह रोजगार की कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, अब स्टेट बैंक के इन शोधकताओं को कौन बताएं कि भैया राजनीतिक पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता में आना और सत्ता में आने का जो रास्ता मुफ्त खोरी से जाता है वो सबसे आसान रास्ता है। पैसा फेंको तमाशा देखो ये तो एक पुराना गीत भी है, अब देखो ना मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू हुई और भाजपा के पक्ष में ऐसे वोट गिरे कि कांग्रेस की लाइ लुट गई ,फिर बिहार में दस दस हजार रुपए लोगों के खाते में डाल दिए गए वहां भी भाजपा की जय जयकार हो गई, बेचारे दूसरे दल हाशिये पर चले गए ,अब जब ऐसा फायदा फ्रीबीज से होता है तो कौन सा राजनीतिक दल है और कौन सी सरकार ऐसी है जो उसका उपभोग नहीं करेगी दूसरी बात फिर पैसा तो अपनी जेब से जाता नहीं है ,सरकारी पैसा है लुटाओ और वोट पाओ इधर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है लेकिन उससे फर्क क्या पड़ने वाला है जो रास्ता दिखा दिया गया है पॉलिटिकल पार्टियों को वे उसी रास्ते पर चलेंगे क्योंकि उन्हें तो सत्ता में आना है और सत्ता में आने का सबसे आसान तरीका अब यही लगने लगा है, रोजगार, भ्रष्टाचार आम आदमी की समस्याएं इन सबसे कोई सत्ता में नहीं आता सत्ता में आता है नोट बांटने से और यह बात सिद्ध भी हो चुकी है और जो बात सिद्ध हो चुकी है तो उससे फिर पीछा कोई भी पॉलीटिकल पार्टी क्यों छुड़ाएगी। अपना भी मानना है कि कर्ज लो और घी पीओ इसी में फायदा है और सारे प्रदेश यही करने में जुटे हुए हैं।सुपर हिट ऑफ द वीक श्रीमती जी ने मायके से श्रीमान जी को कॉल किया और बोली रक्षाबंधन हो गया है अब लेने आ जाओ अरे इतनी जल्दी क्या है पंद्रह अगस्त तक छुट्टी है, दो चार दिन और रह लो श्रीमानजी ने कहा ज्यादा होशियार मत बनो देश आजाद हुआ है तुम नहीं श्रीमती जी ने उत्तर दिया

चैतन्य भट्ट

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संभाजी राव : भारतीय संप्रभुता और सनातन को समर्पित जीवन दर्शन

11 मार्च का वह पावन दिवस मात्र कैलेंडर की एक तिथि नहीं, बल्कि भारतीय स्वाभिमान के उस प्रखर सूर्य के महाप्रयाण का दिन है, जिसने अपने रक्त की अंतिम बूंद से राष्ट्र की अस्मिता को सींचा था। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन उस धधकती ज्वाला के समान है, जिसने औरंगजेब के अहंकार को राख में मिला दिया और हिंदवी साम्राज्य की नींव को वज्र जैसी अडिगता प्रदान की। शिवाजी महाराज के स्वगारोहण के पश्चात जब चारों ओर से संकट के बादल मंडरा रहे थे और मुगलिया सल्तनत की गिद्ध जैसी दृष्टि दक्षिण भारत को निगलने के लिए आतुर थी, तब शंभू राजा ने उस प्रलयंकारी तूफान के विरुद्ध अकेले खड़े होकर वह शौर्य गाथा लिखी, जिसे सुनकर आज भी कायरों की रूह कांप जाती है। उनका संघर्ष केवल राज्य की सीमाओं को बचाने का नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा का महायज्ञ था। अपने नौ वर्षों के संक्षिप्त किंतु अत्यंत तेजस्वी शासनकाल में उन्होंने मुगलों, सिद्दियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों जैसे शत्रुओं को एक साथ धूल चटाकर यह सिद्ध कर दिया कि शेर का शावक कभी झुकना नहीं जानता।

संभाजी महाराज का जीवन प्रतिकूलताओं की उस कसौटी पर कसा गया था, जहाँ साधारण मनुष्य टूट जाता है, परंतु वे निखरकर कुंदन बन गए। एक ओर औरंगजेब अपनी पूरी शक्ति, अपार धन और विशाल सेना के साथ दक्षिण को रौंदने आया था, तो दूसरी ओर स्वराज के भीतर छिपे गद्दारों और षड्यंत्रकारियों का जाल बिछा हुआ था। उन्हें अपनों के विश्वासघात और शत्रुओं के क्रूर आक्रमणों के बीच एक साथ युद्ध लड़ना पड़ा। आर्थिक तंगी, किलों की घेराबंदी और निरंतर सैन्य अभियानों के बावजूद उन्होंने एक भी किला मुगलों के हाथ नहीं लगने दिया। संभाजी महाराज ने युद्ध के मैदान में बिजली की गति से प्रहार किया और मुगलों की रसद काट दी, जिससे औरंगजेब जैसा क्रूर शासक भी वर्षों तक भटकने के लिए विवश हो गया। उनके जीवन का वह अंतिम अध्याय तो मनुष्यता के इतिहास में वीरता की पराकाष्ठा है। जब संगमेश्वर में विश्वासघात के कारण वे पकड़े गए, तो औरंगजेब ने उन्हें अपमानित करने और धर्म परिवर्तन कराने के लिए अमानवीय प्रताड़नाओं का सहारा लिया। उनकी आंखें निकाल ली गईं, जीभ काट दी गई, और खाल तक उधेड़ दी गई, किंतु उस महामानव के मुख से केवल नमो नमः शिवाय और स्वधर्म के प्रति निष्ठा ही प्रकट हुई। उन्होंने मृत्यु को तो गले लगाया, लेकिन अपने स्वाभिमान और पूर्वजों के धर्म को आंच नहीं आने दी। उनकी शहादत ने पूरे महाराष्ट्र में वह ज्वाला प्रज्वलित की, जिसने अंततः मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया।

संभाजी महाराज ने भारतीय इतिहास के समक्ष वह आदर्श स्थापित किया, जो सिखाता है कि राष्ट्र के लिए बलिदान होना किसी पराजय का नाम नहीं, बल्कि अमरता का मार्ग है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब सिद्धांत और प्राणों के बीच चुनाव करना हो, तो सिद्धांतों के लिए प्राणों की आहुति देना ही श्रेष्ठ है। उनके जीवन दर्शन से हमें यह सीख मिलती है कि शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, यदि मन में दृढ़ निश्चय और धर्म के प्रति अटूट आस्था हो, तो उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान और प्रजावत्सल शासक भी थे। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान और वीरता का संगम ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। आज के भारतीय नागरिकों को उनके जीवन से यह गंभीर पाठ पढ़ने की आवश्यकता है कि देश के भीतर पनपने वाली गद्दारी और फूट किसी भी बाहरी आक्रमणकारी से अधिक घातक होती है। इतिहास साक्षी है कि यदि संभाजी महाराज के साथ अपनों ने विश्वासघात न किया होता, तो भारत का चित्र कुछ और ही होता।

पुनः वैसी परिस्थितियां न आएं और हमें फिर किसी वीर योद्धा का बलिदान न देना पड़े, इसके लिए प्रत्येक भारतीय को कुछ कड़े संकल्प और ऐहतियातें बरतने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अटूट निष्ठा। हमें जाति, पंथ और क्षेत्रीयता की उन दीवारों को ढहाना होगा जो हमें भीतर से खोखला करती हैं और बाहरी ताकतों को हस्तक्षेप का अवसर देती हैं। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब-जब हम बंटे हैं, तब-तब हमें लूटा और प्रताड़ित किया गया है। आज के युग में वैचारिक युद्ध और छद्म वेश में छिपे शत्रुओं को पहचानना अनिवार्य है। हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था और सामरिक शक्ति को इतना सुदृढ़ करना होगा कि शत्रु हमारे विरुद्ध विचार करने से पहले भी सौ बार सोचे। स्वधर्म और स्वसंस्कृति के प्रति हीनभावना को त्यागकर गर्व के साथ अपनी जड़ों से जुड़ना ही संभाजी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नागरिक के रूप में हमें सतर्क रहना होगा कि कहीं हमारी व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि राष्ट्र के हितों से ऊपर न हो जाए। हमें भ्रष्टाचार और गद्दारी जैसी दीमकों को समाज से उखाड़ फेंकना होगा। संभाजी महाराज का रक्त हमारे भीतर इस चेतना का संचार करे कि भारत भूमि का प्रत्येक कण पवित्र है और इसकी रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना है। जिस दिन हम सामूहिक रूप से यह संकल्प ले लेंगे कि राष्ट्र प्रथम, उस दिन कोई भी औरंगजेब इस पावन धरा की ओर आंख उठाकर देखने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। आइए, 11 मार्च को उस महान बलिदानी को नमन करते हुए हम अपने भीतर के राष्ट्रप्रेम को जागृत करें और एक ऐसे समर्थ भारत का निर्माण करें जो विश्व में अपनी वीरता और ज्ञान के लिए पुनः शिरोमणि बने। धर्मवीर संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, यदि हम उनके संघर्ष से सीख लेकर स्वयं को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दें। जय शिवाजी, जय शंभूराजे !

डॉ. राघवेंद्र शर्मा

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर देती?

भारत में जब किसी राज्य में कानून-व्यवस्था या राजनीतिक टकराव को लेकर विवाद बढ़ता है, तो अक्सर यह सवाल उठता है कि केंद्र सरकार या राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को क्यों नहीं हटा देते? हाल के समय में भी पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर ऐसी चचाएँ सुनाई देती हैं। लेकिन भारतीय संविधान में राज्य सरकार को बर्खास्त करना इतना सरल या मनमाना निर्णय नहीं है। इसके लिए स्पष्ट संवैधानिक प्रक्रिया और ठोस कारण आवश्यक होते हैं। अभी हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 7 मार्च, 2026) को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद द्वारा आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में भाग लेने गईं थीं जहां कई अव्यवस्थायें देखने को मिलीं। जिस लेकर राष्ट्रपति ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इस पर विपक्ष का कहना था कि वहां चुनाव है इसलिए भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पदों का भी राजनीतिक इस्तेमाल कर रही हैं ? जबकि राष्ट्रपति का पद राजनीति से बहुत ऊपर है। अब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाना तो तय है।

यह मुद्दा इतना गर्म हो गया था कि दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राष्ट्रपति जी के अपमान और संथाल संस्कृति के साथ किए गए लापरवाही भरे व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जो भी लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास करता है, वो इस घटना से बहुत निराश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति जी खुद आदिवासी समुदाय से हैं, और उन्होंने जो दर्द और पीड़ा व्यक्त की है उसने भारत के लोगों को बहुत दुःखी किया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं और राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए उनका प्रशासन जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय के साथ पश्चिम बंगाल सरकार इतना लापरवाही भरा व्यवहार कर रही है। इस कार्यालय की पवित्रता का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी को सद्बुद्धि आएगी।

अब ऐसे में भारत की राष्ट्रपति, वर्तमान में द्रोपदी मुर्मु, देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। हालांकि वे अधिकांश मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही निर्णय लेती हैं। किसी राज्य की सरकार को हटाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आता है, जिसे आम तौर पर राष्ट्रपति शासनइ कहा जाता है। इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया है।पश्चिम बंगाल में वर्तमान में सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी कर रही हैं। यदि राज्य में राजनीतिक हिंसा, प्रशासनिक विफलता या अन्य गंभीर स्थिति की शिकायतें होती भी हैं, तब भी केवल आरोपों या राजनीतिक मतभेद के आधार पर सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट, केंद्र सरकार का आकलन और अंततः संसद की मंजूरी जैसी प्रक्रियाएँ जरूरी होती हैं।

इतिहास बताता है कि अनुच्छेद 356 का कई बार राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग हुआ है। इसी कारण एस-आर बोम्माई वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेगा और इसे मनमाने तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद राज्यों की चुनी हुई सरकारों को हटाना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो गया है।

लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हटाने का सबसे बड़ा अधिकार अंततः जनता के पास ही होता है। यदि किसी राज्य की सरकार से असंतोष है, तो उसका समाधान चुनाव के माध्यम से किया जाता है। इसलिए केवल राजनीतिक विवाद या आरोपों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा सीधे राज्य सरकार को बर्खास्त करना न तो संवैधानिक रूप से उचित है और न ही लोकतांत्रिक परंपरा के अनुकूल। इस प्रकार, पश्चिम बंगाल सरकार को हटाने का सवाल केवल राजनीतिक इच्छा का नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मयार्दाओं का विषय है। जब तक यह साबित न हो जाए कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है, तब तक किसी भी सरकार को बर्खास्त करना संभव नहीं होता।

अब सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल सरकार पर नाराज होने की चर्चा मुख्यतः राज्य में कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक टकराव और केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े मुद्दों के कारण उठती रही है। हाल के समय में कुछ घटनाओं ने इस तनाव को और बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल में कई बार राजनीतिक हिंसा, चुनावी टकराव और साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएँ सामने आती रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाएँ राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की अपेक्षा करती हैं। जब स्थिति गंभीर मानी जाती है, तो राष्ट्रपति तक इसकी रिपोर्ट पहुँचती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं–जैसे केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई, राज्यपाल के साथ विवाद, और नीतिगत फैसले। इन राजनीतिक टकरावों से भी स्थिति तनावपूर्ण बनती है।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल समय-समय पर राज्य की स्थिति को लेकर केंद्र को रिपोर्ट भेजते रहे हैं। यदि रिपोर्ट में प्रशासनिक विफलता या गंभीर कानून-व्यवस्था की समस्या बताई जाती है, तो राष्ट्रपति का ध्यान उस ओर जाता है। राष्ट्रपति का काम सीधे गुस्सा दिखाना नहीं होता, बल्कि संविधान की रक्षा करना होता है। अगर किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था बिगडऩे की आशंका हो, तो राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर कदम उठा सकते हैं (जैसे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन)।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नाराजगी की चर्चा असल में पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था, राजनीतिक संघर्ष और केंद्र-राज्य संबंधों के तनाव से जुड़ी है। हालांकि राष्ट्रपति स्वयं राजनीतिक बयान कम ही देती हैं और अधिकतर कार्रवाई संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही होती है।

सौरभ वार्ष्णेय

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

सूडोकु नवताल- 7447

★★★★★ कठिनतम

				6	8	5		
	1						2	
		2						8
			4					9
6				5				1
2					3			
5						3		
	8						6	
		4	9	1				

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7446 का हल

2	4	6	7	9	3	5	8	1
3	1	5	2	8	6	4	7	9
7	8	6	1	5	4	2	3	6
6	5	7	9	3	8	1	4	2
9	3	1	4	7	2	8	6	5
4	2	8	6	1	5	7	9	3
1	9	2	3	4	7	6	5	8
5	7	3	8	6	1	9	2	4
8	6	4	5	2	9	3	1	7

दैनिक पंचांग

11 मार्च 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

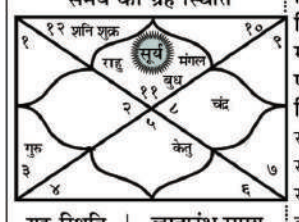

बुधवार 2026 वर्ष का 70 वा दिन
दिशाशूल उत्तर **ऋतु** शिशिर।
विक्रम संवत् 2082 **शक संवत्** 1947
मास चैत्र (दक्षिण भारत में फाल्गुन)
पक्ष कृष्ण
तिथि अष्टमी 04.20 बजे रात्र को समाप्त। **नक्षत्र** ज्येष्ठा 22.00 बजे को समाप्त। **योग** वज्र 09.12 बजे को समाप्त। **करण** बालव 15.09 बजे तदनन्तर कौलव 04.20 बजे रात्र को समाप्त। **चन्द्रायु** 21.5 घण्टे
रवि क्रान्ति दक्षिण 03° 48'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1872645
जूलियन दिन 2461110.5
कलियुग संवत् 5128
कल्पारंभ संवत् 1972949128
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885128
वीरनिर्वाण संवत् 2552
हिजरी सन् 1447
महीना रमजान **तारीख** 21
विशेष शीतला अष्टमी, कालाष्टमी।

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	कुंभ में	मीन	06.28 बजे से
चंद्र	वृश्चिक में	मेष	07.58 बजे से
मंगल	कुंभ में	वृष	09.38 बजे से
बुध	कुंभ में	मिथुन	11.37 बजे से
गुरु	मिथुन में	कर्क	13.50 बजे से
शुक्र	मीन में	सिंह	16.06 बजे से
शनि	मीन में	कन्या	18.18 बजे से
राहु	कुंभ में	तुला	20.29 बजे से
केतु	सिंह में	वृश्चिक	22.43 ब.से
राहुकाल 12.00 से 1.30 बजे तक		धनु	00.59 बजे से
		मकर	03.05 बजे से
		कुंभ	04.51 बजे से

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
लाभ	05.54 से	07.22 बजे तक	उद्वेग	05.41 से	07.12 बजे तक
अमृत	07.22 से	08.51 बजे तक	शुभ	07.12 से	08.44 बजे तक
काल	08.15 से	10.19 बजे तक	अमृत	08.44 से	10.16 बजे तक
शुभ	10.19 से	11.47 बजे तक	चर	10.16 से	11.47 बजे तक
रोग	11.47 से	01.16 बजे तक	रोग	11.47 से	01.19 बजे तक
उद्वेग	01.16 से	02.44 बजे तक	काल	01.19 से	02.51 बजे तक
चर	02.44 से	04.12 बजे तक	लाभ	02.51 से	04.23 बजे तक
लाभ	04.12 से	05.41 बजे तक	उद्वेग	04.23 से	05.54 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

संक्षिप्त खबरें

तमिलनाडु में मच्छरमार अगरबत्ती से घर में लगी आग, परिवार के तीन सदस्यों की मौत

चेंगलपट्टु (तमिलनाडु), (एजेंसी) : तमिलनाडु में चेंगलपट्टु जिले के कूडुवांचेरी के कन्नीवाक्कम इलाके में एक घर पर मच्छरमार (मच्छर भगाने वाली) अगरबत्ती से लगी आग में एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक है।

कन्नीवाक्कम इलाके के तैंतीस वर्षीय पार्थिबन और उनके परिवार के लिए बीती रात को घर पर आराम से नींद आने के लिए मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती को जलाकर सोना प्राणघातक साबित हुआ। अगरबत्ती की वजह से आग लगने से धुआं फैल गया। इस धुएं से पार्थिबन, उनकी पत्नी जयचित्रा (29) और ढाई साल की बेटी जयश्री का दम घुट गया। तड़के घर से धुआं निकलते देख पड़ोसियों ने तुरंत मराइमलाई नगर अग्निशमन विभाग और कूडुवांचेरी पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचते ही घर का दरवाजा तोड़कर आग बुझाई। पुलिस ने शव चेंगलपट्टु सरकारी अस्पताल भेजे दिए हैं। कूडुवांचेरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हर कोण से जांच की जा रही है।

कैबिनेट : जल जीवन मिशन को मिला विस्तार, सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को मिलेगा नल कनेक्शन

नई दिल्ली,(एजेंसी) : केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अतिरिक्त आवंटन और पुनर्गठित कार्यान्वयन शामिल है।

जल जीवन मिशन 2.0 के तहत दिसंबर 2028 तक देशभर के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। जेजेएम का पुनर्गठन और पुनर्रचना बुनियादी ढांचे के निर्माण से हटकर सेवा वितरण पर केंद्रित होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।

मंत्रिमंडल ने योजना खर्च को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय सहायता 3.59 लाख करोड़ रहेगी। यह 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। मंत्री के अनुसार योजना का क्रियान्वयन ऐसे होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

इसके अलावा एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा ह्यसुजलम भारतह्न बनाया गया है। यह स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण करेगा।

कैबिनेट : जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी निर्माण की पूंजी लागत में संशोधन

नई दिल्ली, (एजेंसी) : केन्द्र सरकार ने जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण की कुल पूंजी लागत में संशोधन किया है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज की बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-सोहना शाखा से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए 3630.77 करोड़ रुपये की संशोधित कुल लागत को मंजूरी दी।मंत्री के अनुसार 31.42 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से हवाई अड्डे तक सीधी और उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह मार्ग पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस-वे, यमुना एक्सप्रेस-वे और समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर से होकर गुजरता है।यह एलिवेटेड कॉरिडोर शहरी परिवर्तन, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए रणनीतिक सहायक के रूप में कार्य करेगा।वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना का लगभग 11 किलोमीटर लंबा हिस्सा एलिवेटेड हाईवे के रूप में विकसित किया जाना है। यह डीएनडी-बल्लभगढ़ बाईपास और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण खंड है और इसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ता है।उन्होंने बताया कि यह कॉरिडोर फरीदाबाद मास्टर प्लान, 2031 के तहत उच्च घनत्व वाले शहरी विकास और भविष्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए निर्धारित क्षेत्र से होकर गुजरता है। प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर की अतिरिक्त लागत 689.24 करोड़ रुपये है और हरियाणा सरकार ने एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 450 करोड़ रुपये वहन करने पर सहमति जताई है।

भारत ने मोजाम्बिक में बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी राहत सामग्री

नई दिल्ली, (एजेंसी) : पूर्वी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के मध्य और दक्षिणी प्रांतों में आई बाढ़ से मची तबाही के बीच भारत ने मंगलवार को व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया है।विदेश मंत्रालय के अनुसार संकट की इस घड़ी में मोजाम्बिक के साथ भारत ने एकजुटता दिखाते हुए यहां के लिए खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं सहित अन्य बहुआयामी सहायता प्रदान की है। इसमें तत्काल खाद्य सहायता के रूप में 500 मीट्रिक टन चावल और 10 मीट्रिक टन अन्य राहत सामग्री भारतीय नौसेना के जहाज के जरिए भेजी गई है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ₹भारत हिंद

रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के लिए मिलिट्री विजन डॉक्यूमेंट' रोडमैप जारी किया

भविष्य की युद्ध चुनौतियों के लिए सेना को आधुनिक, इंटीग्रेटेड और तकनीक से लैस करने पर जोर

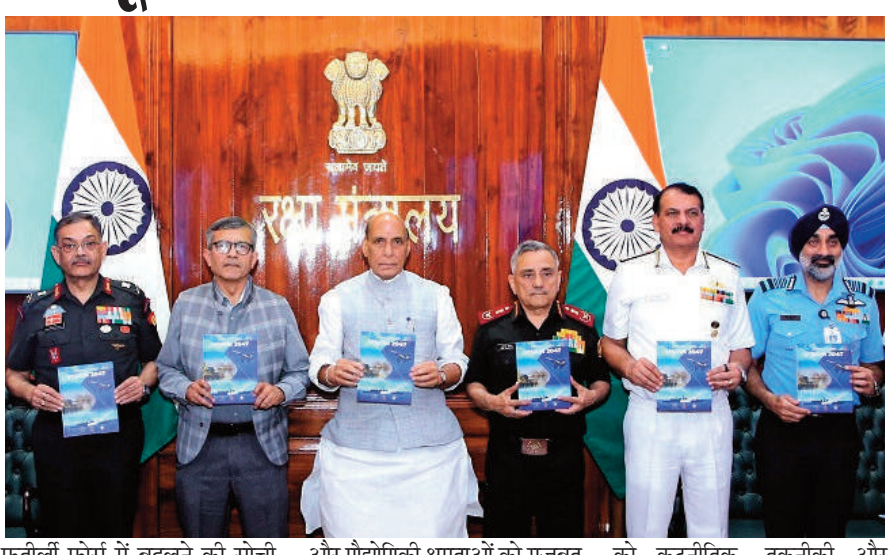

नई दिल्ली, (एजेंसी) :रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को साउथ ब्लॉक में भारतीय सेना के लिए ह्यडिफेंस फोर्सेज विजन' रोडमैप जारी किया। यह बड़ा ब्लूप्रिंट हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने रक्षा बलों को आधुनिक, इंटीग्रेटेड और तकनीक से लैस सेना में बदलने के लिए तैयार किया है, जो 2047 तक भारत के विकसित देश बनने के सपने को पूरा करने में मदद कर सके। यह डॉक्यूमेंट भविष्य की युद्ध चुनौतियों के लिए ढलने वाली सेना बनाने के लिए इनोवेशन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और मॉडर्न ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के महत्व पर भी जोर देता है।इस विजन डॉक्यूमेंट में सशस्त्र बलों में जरूरी सामरिक सुधारों, क्षमता बढ़ाने और संगठनात्मक बदलावों के बारे में बताया गया है, ताकि बदलते भू-रणनीतिक, तकनीकी और सुरक्षा माहौल से अच्छे से निपटा जा सके। इसमें सेना को एक इंटीग्रेटेड, मल्टी-डोमेन और फुतीर्ली फोर्स में बदलने की सोची गई है, जो दुश्मनों को रोकने, हर तरह के झगड़े में जवाब देने और तेजी से बदलते ग्लोबल और रीजनल हालात के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक हितों की रक्षा करने में काबिल हो। इस विजन का एक मुख्य हिस्सा सेनाओं के बीच तालमेल और तालमेल पर जोर देना है, जिससे प्लानिंग, ऑपरेशन और क्षमता विकास में ज्यादा तालमेल को बढ़ावा मिलेगा।रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस विजन में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जो देश की खास सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से स्वदेशी तकनीक और समाधान अपनाने को बढ़ावा देता है। घरेलू रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करने से ऑपरेशनल तैयारी बढ़ने और देश की ग्रोथ में योगदान देने की उम्मीद है। विजन डॉक्यूमेंट में शॉर्ट-टर्म, मिड-टर्म और लॉन्ग-टर्म टाइमलाइन में साफ तौर पर प्राथमिकता वाले क्षमता लक्ष्यों के साथ एक कैलिब्रेटेड रोडमैप अपनाया गया है। यह विश्व स्तरीय डिफेंस फोर्स बनाने के लिए जरूरी सैन्य क्षमताओं, संस्थागत सुधारों और रणनीतिक स-ाझेदारी के विकास में सहयोग करेगा।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों की जटिलता को पहचानते हुए यह विजन डॉक्यूमेंट पूरे देश के नजरिए की जरूरत पर जोर देता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पक्की करने के लिए सैन्य ताकत को कूटनीतिक, तकनीकी और आर्थिक ताकत के साथ जोड़ा जाएगा। लगातार सुधारों, इनोवेशन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के जरिए इसका मकसद यह पक्का करना है कि भारत की आजादी की सौवीं सालगिरह तक देश की सेना दुनिया भर में सम्मानित, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और लड़ाई के लिए तैयार मिलिट्री के तौर पर खड़ी हो, जो मजबूत विकसित भारत में योगदान दे।

इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे

बेंगलुरु में वाणिज्यिक एलपीजी की कमी से होटल उद्योग संकट में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

बेंगलुरु, (एजेंसी) : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति में आई अचानक बाधा को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने आशंका जताई कि यदि जल्द ही आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो शहर के कई होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग प्रतिष्ठानों को अपना संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 9 मार्च को जारी आदेश के अनुसार एलपीजी उत्पादन को प्राथमिकता देते हुए तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे उपलब्ध एलपीजी की आपूर्ति मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं को करें। घरों में रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, इस आदेश के लागू होने के बाद बेंगलुरु में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की अचानक कमी देखी जा रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट संगठनों ने सरकार को बताया है कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। इससे होटल, छोटे भोजनालय, मेस और कैटरिंग सेवाओं के संचालन पर गंभीर असर पड़ने लगा है। यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो अनेक प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है।

पत्र में मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि बेंगलुरु में लाखों लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराने वाले छोटे होटल, मेस और सामुदायिक रसोई का बड़ा नेटवर्क है। इन प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए वाणिज्यिक एलपीजी पर ही निर्भरता रहती है। तेल विपणन कंपनियों के साथ हुई चर्चा के आधार पर उन्होंने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में शहर की वाणिज्यिक एलपीजी मांग को पूरा करने के लिए तीन प्रमुख कंपनियां आपूर्ति करती हैं।इनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) प्रतिदिन लगभग 500 से 550 मीट्रिक टन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) करीब 300 मीट्रिक टन और भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) लगभग 230 मीट्रिक टन एलपीजी की आपूर्ति करती रही हैं। इन आपूर्तियों में अचानक आई रुकावट से होटल उद्योग के साथ-साथ कैटरिंग संस्थान और अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संकट का असर केवल होटल उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि घरों से दूर रहकर पढ़ाई या नौकरी करने वाले छात्रों और कामकाजी लोगों पर भी पड़ेगा, जो रोजमर्रा के भोजन के लिए होटल और मेस पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा विवाह मंडप, छात्रावास, सामुदायिक भवन और विभिन्न कार्यक्रम स्थल भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि भोजन तैयार करने के लिए वे वाणिज्यिक एलपीजी का ही उपयोग करते हैं।

कोलकाता पोर्ट के ऐतिहासिक बासक्यूल पुल के नवीनीकरण को मंजूरी

नई दिल्ली, 10 मार्च (हि.स.)। केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट स्थित ऐतिहासिक बासक्यूल पुल के नवीनीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 117.54 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के डॉक सिस्टम की सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सबानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 'विरासत भी, विकास भी' की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। यह परियोजना एक महत्वपूर्ण विरासत संपत्ति को संरक्षित करते हुए आधुनिक तकनीक से उसे सुरक्षित, तेज और अधिक कुशल पोर्ट संचालन के लिए तैयार करेगी। मंत्रालय ने बताया कि करीब छह दशक पुराने इस दो लेन के बासक्यूल पुल का निर्माण मूल रूप से वाग्नर-बिरो ब्रिज सिस्टम्स एजी ने किया था। अब इसमें व्यापक संरचनात्मक मजबूती और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल अपग्रेड किए जाएंगे। प्रस्ताव का मूल्यांकन 16 फरवरी 2026 को मंत्रालय की डेलीगेटेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में किया गया था। 117.54 करोड़ रुपए की इस परियोजना को लगभग 41 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सागरमाला कार्यक्रम के तहत मिलेगी। ह्न

परियोजना का क्रियान्वयन रेल विकास निगम लिमिटेड

अयोध्या पहुंचा 11 सदस्यीय दक्षिण कोरियाई दल, मातामही रानी हो को किया नमन

महापौर ने किया स्वागत, स्मारक के विकास में सहयोग का वादा

रानी हो के कारण अयोध्या को मिली वैश्विक पहचानः त्रिपाठी

अयोध्या, 10 मार्च (हि.स.)। दक्षिण कोरिया का 11 सदस्यीय दल मंगलवार को अयोध्या पहुंचा और राजकुमारी सूरीरत्ना (दक्षिण कोरिया के गया राज्य की महारानी हेलो ह्वांग-ओक) के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये। इस दौरान महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने अपनी पत्नी श्रीमती राजलक्ष्मी त्रिपाठी के साथ कोरियाई प्रतिनिधि मंडल का अंग वस्त्र एवं प्रभु श्रीराम की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान महापौर ने रानी हो मेमोरियल पार्क के विकास में हर संभव सहयोग का वादा किया। हाल ही में स्मारक नगर निगम ने पर्यटन विभाग से हस्तगत किया है।

दक्षिण कोरिया गणराज्य का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इंचियोन ली क्वान एसोसिएशन के अध्यक्ष ली जिन ओके के नेतृत्व में अपनी मातामही रानी हो से जुड़ी स्मृतियों को ताजा करने मंगलवार को अयोध्या पहुंचा। दुभाषिया के माध्यम से हुई बातचीत में प्रतिनिधिमंडल ने रानी हो मेमोरियल पार्क में पूजा स्थल के विकास की आवश्यकता जताई। महापौर ने स्मारक के विकास में हरसंभव सहयोग का वादा किया। उन्होंने इसके लिए भारतीय दूतावास के माध्यम से पत्राचार करने का सुझाव दिया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि आगामी 6 अक्टूबर को सौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रानी हो को नमन करने अयोध्या आएगा। उन्होंने अप्रैल में दक्षिण कोरिया में हो रहे कार्यक्रम में आने का निमंत्रण महापौर को दिया।

एलपीजी की कमी से बेंगलुरु का होटल उद्योग संकट में, केंद्र से तत्काल आपूर्ति बहाल करने की मांग

बेंगलुरु, (एजेंसी) :पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब देश के होटल उद्योग पर भी दिखने लगा है। ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के कारण वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से बेंगलुरु के होटल कारोबारियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। शहर के कई होटल गैस की कमी के कारण बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं।

होटल संचालकों का कहना है कि एलपीजी की कमी के चलते कॉफी, चाय, नाश्ता और भोजन जैसी सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। होटल व्यवसाय पूरी तरह वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर करता है और इसके बिना होटल संचालन करना संभव नहीं है। ऐसे में गैस आपूर्ति बाधित होने से होटल उद्योग की गतिविधियां ठप पड़ने का खतरा बढ़ गया है।

बेंगलुरु होटल मालिक संघ के अध्यक्ष पी.सी. राव ने मंगलवार को कहा कि गैस की कमी के कारण होटल उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि कई होटल संचालकों को पर्याप्त एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे होटल संचालन में भारी दिक्कतें आ रही हैं।

हालांकि, केंद्र सरकार ने पहले यह दावा किया था कि देश में 60 से 70 दिनों तक का एलपीजी भंडार उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति में आई बाधा ने होटल कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। होटल एसोसिएशन ने राज्य सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और जल्द समाधान निकालने की मांग की है।होटल संचालकों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भी आग्रह किया है कि वे केंद्र सरकार से बातचीत कर वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति जल्द बहाल कराने के लिए दबाव बनाएं, ताकि होटल उद्योग को राहत मिल सके।

इस मुद्दे को लेकर बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी पहल की है। उन्होंने शहर के होटलों में एलपीजी सिलेंडरों की कमी को गंभीर बताते हुए इस मामले को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया है।सांसद ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट उद्योग अपने दैनिक भोजन पकाने के लिए मुख्य रूप से वाणिज्यिक एलपीजी पर निर्भर है, इसलिए इस क्षेत्र के लिए गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

तेजस्वी सूर्या ने सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी साझा करते हुए कहा कि बेंगलुरु के होटल उद्योग को राहत दिलाने के लिए केंद्र से जल्द कार्रवाई की उम्मीद है।

दिल्ली-एनसीआर का अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

नई दिल्ली, : उत्तर और मध्य भारत में गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। जहां मैदानी इलाकों में पारा तेजी से चढ़ रहा है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। यहां गर्मी की स्थिति 13 मार्च तक बनी रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार आने वाले कुछ दिन उत्तर और मध्य भारत के लिए काफी गर्म रहने वाले हैं। राजधानी के अलग-अलग इलाकों में 13 मार्च तक गर्मी की यही स्थिति बनी रहेगी।

आईएमडी के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और झारखंड के कई हिस्सों में तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मध्य भारत में पश्चिमी राजस्थान विदर्भ सौराष्ट्र और कच्छ में पारा 38-41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

दक्षिण और पश्चिम के केरल तमिलनाडु मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में तापमान 35-38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम जैसे राज्यों में अधिकतम तापमान 14-18 डिग्री दर्ज किया गया। तटीय इलाकों (गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल) में न्यूनतम तापमान 18-22 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 16 मार्च तक वर्षा और हिमपात होने के आसार हैं। 10-11 मार्च को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हो सकती है।

मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

यूसीसी लागू करने का सही समय आ गया

नई दिल्ली(एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में अब इस विषय पर लंबित से विचार करने का समय आ गया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शरीयत कानून की धाराओं को रद्द करने जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अंतिम फैसला लेना विधायिका का अधिकार क्षेत्र है।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें जॉयमाल्या बागची और आर. महादेवन भी शामिल थे। पीठ 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इन्हें मुस्लिम महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि न्यायालय शरियत कानून के उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों को रद्द कर देता है, तो इससे एक कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य स्पष्ट कानून मौजूद नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण से कहा कि सुधार की जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाना उचित नहीं होगा जिससे महिलाओं को वर्तमान से भी कम अधिकार मिल जाएं। उन्होंने पूछा कि यदि 1937 का शरियत कानून समाप्त हो जाता है तो उसके स्थान पर क्या व्यवस्था लागू होगी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने भी कहा कि याचिका में भेदभाव का मुद्दा मजबूत है, लेकिन इस विषय पर निर्णय लेना संसद के लिए अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता लागू करने का दायित्व विधायिका को दिया गया है।

अदालत ने यह भी कहा कि पहले भी कई बार न्यायालय संसद से समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार करने की सिफारिश कर चुका है। पीठ के अनुसार, सामाजिक और व्यक्तिगत कानूनों में व्यापक सुधार के लिए विधायी प्रक्रिया ही सबसे उपयुक्त रास्ता है।

केंद्र सरकार की देखभाल परिस्थिति तंत्र पर वेबिनार में बोले जयंत चौधरी- सामाजिक और आर्थिक अवसर दोनों

नई दिल्ली, (एजेंसी) :केंद्रीय बजट के बाद केंद्र सरकार ने 'भारत के देखभाल परिस्थिति को मजबूत करनाः 1.5 लाख बहुकुशल देखभाल करने वालों को कुशल बनाना' विषयक वेबिनार आयोजित कर स्वास्थ्य सेवा, कल्याण और संबद्ध सेवाओं में मानकीकृत पाठ्यक्रम और बहु-कौशल मॉड्यूल के जरिए देखभाल करने वालों के लिए रोजगार मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह सत्र केंद्रीय बजट 2026-27 की उस घोषणा पर केंद्रित रहा जिसमें देखभाल क्षेत्र के लिए एक संरचित और पेशेवर कार्यबल तैयार करने की बात कही गई।

केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के अनुसार, सत्र में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी, मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी, मंत्रालय की वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार मनीषा सेन शर्मा, विदेश मंत्रालय के अपर सचिव प्रशांत पिसे, असम के प्रमुख सचिव ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी, एशियाई विकास बैंक की निदेशक मिया ओका, यूनिसेफ की जियोर्जिया वरिस्को, अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड के सीईओ डॉ. श्रीनिवास राव पुलिजाला, पोर्टिया मेडिकल के निदेशक के. गणेश, सोडेक्सो इंडिया के संदीप कुमार, मोबाइल क्रेच की सीईओ सुमित्रा मिश्रा और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया।

जयंत चौधरी ने कहा कि देखभाल अर्थव्यवस्था भारत के लिए सामाजिक प्राथमिकता और आर्थिक अवसर दोनों है। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख बहुकुशल देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित करने की पहल से एक पेशेवर इकोसिस्टम तैयार होगा जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार अवसर पैदा करेगा। उन्होंने जापान और इजराइल जैसे देशों के साथ साझेदारी के जरिए वैश्विक कौशल राजधानी बनने की दिशा में भारत की यात्रा को मजबूत बताया।

देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि बजट घोषणा बहुकुशल देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने पेशेवर प्रशिक्षण, मानकीकृत प्रमाणन और विश्वसनीय करियर मार्ग को देखभाल करने वालों की गरिमा और पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया।

मनीषा सेन शर्मा ने कहा कि यह पहल न केवल घरेलू मांग बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रशिक्षित देखभाल पेशेवरों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है।

शारीरिक फिटनेस से बढ़ती है गणित की समझ

गणित से कतराने वाले बच्चों के माता-पिता के लिए एक अच्छी खबर है। शोधकर्ताओं का कहना है कि शारीरिक फिटनेस बच्चों को गणित समझने में सहायक होती है। व्यायाम करने वाले बच्चे गणित में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। शोध में पाया गया कि 9-10 साल के जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में गणित में उनका प्रदर्शन अच्छा होता है। ऐसे बच्चों में 'ग्रे मैटर' पतला हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलेनॉय की शोधकर्ता लौरा चडोक हेमैन ने बताया कि पहले के शोधों में पाया गया है कि 'ग्रे मैटर' के पतलेपन का सीधा संबंध तर्कशक्ति और सोचने की क्षमता से होता है। उन्होंने कहा कि पहली बार हम यह जानने में सफल हुए हैं कि व्यायाम इस प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। शोध में 48 बच्चों को शामिल किया गया था।

बचपन को बनाएं खुशहाल

बच्चों के तनाव को हल्के में न लें, क्योंकि उनकेमस्तिष्क पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ता है। वॉशिंगटन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कान्सिन-मैडिसन के शोधकर्ताओं के एक दल ने यह पाया कि उपेक्षा और शारीरिक उत्पीडन से पैदा होने वाले तनाव का बच्चे पर नकारात्मक और स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार ऐसे अनुभवों से बच्चे केमस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है। इससे उनकी याद रखने की क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसे बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संतुलन का भी अभाव देखने को मिलता है। यही नहीं युवा होने के बाद ऐसे बच्चों की सेहत, कॅरियर और दांपत्य जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव नजर आता है। इस अध्ययन में सौ से अधिक बच्चों को शामिल किया गया था, जिनकी उम्र बारह वर्ष थी और कई वजहों से उनका बचपन तनावग्रस्त था। शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि आप चाहती हैं कि आपका बच्चा एक समझदार इंसान बने और वह अपनी पूरी जिंदगी हंसी-खुशी से व्यतीत करे तो आपको उसका बचपन खुशहाल बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।

बच्चों को ऐसे सिखाएं हावभाव से भाषा

आमतौर पर माना जाता है कि बच्चों में जल्दी सीखने की क्षमता होती है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। एक अध्ययन के हिसाब से इन तरीकों में 'जेसचर्स' यानी स्वतः इशारे बच्चों को भाषा सीखनें में काफी मददगार हो सकते हैं। स्वतः यानी अपने आप होने वाले इन इशारों से बच्चों को स्पोकन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज़ को सीखने में आसानी होगी। बच्चे अपनी बात कहने के लिए स्वाभाविक इशारों से अपनी बात ज्यादा आत्मविश्वास से कह पाते हैं।

बच्चों की अभिव्यक्ति करें प्रभावी

यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफ़ेसर सुसैन गोल्डिन के मुताबिक हाथों के इशारों और शब्दों का संयोजन बच्चों को उनकी बात एक प्रवाह में कहने में मदद करता है। इस अध्ययन के नतीजों से पता चलता है कि बोलने से पहले बच्चों को अपने विचारों को समझने में आसानी होती है जिससे वे खुलकर अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं। इस अध्ययन में सुसैन ने जांचा की इशारे किस तरह बच्चों में भाषा को सीखने में मदद करते हैं। उनके मुताबिक स्वतः इशारे भाषा को समझने का एक आसान तरीका है और कोई भी बातचीत करने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर कई मौकों पर ये इशारे ही खुद एक भाषा का रूप ले लेते हैं।

मां- बाप से सीखते हैं इशारे

इसके साथ ही प्रोफ़ेसर सुसैन ने स्पोकन लैंग्वेज पर भी शोध किया है। इस अध्ययन में उन्होंने ऐसे बच्चों का अध्ययन किया जो अपने पैरेंट्स के इशारों से सीखते हैं। सुसैन ने पाया कि बच्चे अपने मां-बाप के इशारों की आदत को जल्दी अपनाते हैं। ये बच्चों की प्रवाह में बोलने की क्षमता बढ़ाने जैसा ही है। इन इशारों में बच्चों को सीख मिलती है। ये उसी तरह से कारगर है जैसे शब्दों के साथ हाथों के इशारों का प्रयोग उन्हें बेहतर अभिव्यक्त करने में मदद करता है। घर के माहौल में अपने आप ही ये इशारे बच्चों की भाषा में आ जाते हैं। इससे बच्चों में अपने विचारों को आसानी से प्रकट करने की क्षमता बढ़ती है।

मूक-बधिर बच्चों के लिए वरदान

इस अध्ययन में आम बच्चों के अलावा प्रोफेसर सुसैन ने मूक-बधिर बच्चों की भाषा को भी समझा। इस केस में उन्होंने अध्ययन किया कि न सुन पाने वाले बच्चों में उनकी ये अक्षमता कैसे उन्हें बोलचाल की भाषा सीखने से रोकती है। साथ ही उन बच्चों पर भी जिनके मां-बाप ने किसी भी तरह से साइन लैंग्वेज को नहीं अपनाया। उन्होंने पाया कि ये बच्चे में घर में बने सिस्टम यानी कि 'होमोसाइन' का प्रयोग करते हैं। होमोसाइन, साइन लैंग्वेज को सिखाने की दिशा में पहला कदम है। कोई और साधन न होने की स्थिति में स्वतः इशारे बच्चों में खुद की भाषा बनाने के लिए भाषाई रूपों और कार्यों का एक कारगर तरीका साबित होता है।

मोबाइल पर बच्चों की सिक्योरिटी

हर समय बच्चों के हाथों में मोबाइल देखकर कई अभिभावक नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन इस खबर को पढने के बाद वे खुद चाहेंगे कि उनके बच्चों के पास उनका मोबाइल 24&7 रहे।

बच्चे जब आंखों से दूर होते हैं तो आपको लगातार उनकी चिंता रहती है। आपकी इसी चिंता को दूर करती है बी सेफ मोबाइल एप्लिकेशन। ये एप्लिकेशन आपके बच्चे की सुरक्षा की हर जानकारी देती है। इस एप्लिकेशन को डिवेल्प करने वाली कोई बड़ी कंपनी नहीं है। ये एप्लिकेशन एक आम मां की सोच की उपज है जो अपनी बेटी की चिंता में अक्सर परेशान रहती थी। सिल्जी वैलेस्टेड नाम की महिला ने बी सेफ एप्लिकेशन के आइडिया को जन्म दिया है जिसके बाद मोबाइल के जरिये हर अभिभावक अपने बच्चे से लगातार जुड़े रह सकते हैं।

आइये जानते हैं कि बी सेफ किस तरह आपके बच्चों को मुसीबतों से दूर रख सकती है। इस एप्लिकेशन को मोबाइल पर डाउनलोड करने के बाद आपका पहला कदम होगा अपना एकाउंट खोलना। बी सेफ में एकाउंट खोलने की काफी आसान प्रक्रिया है। इसके लिए आपको सिर्फ अपना नाम, देश का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल पता और पासवर्ड देना होता है। एक बार आपका एकाउंट खुल जाता है आप आसानी से उनके नाम अपने लिस्ट में जोड़ सकते हैं जिन्हें आप मुसीबत के समय मदद के लिए बुलाना चाहते हैं। इन नाम के चयन करते ही एक एसएमएस उन सभी लोगों के पास जाता है जिसमें बताया जाता है कि मुसीबत के समय उनकी क्या भूमिका होगी।

बी सेफ में सबसे अहम फीचर है इसका एसओएस बटन। ये फीचर खास तौर से जिंदगी के खतरे में पडने की हालत में एलर्ट जारी करने के लिए तैयार किया गया है। इस बटन को दबाते ही एक मेसेज अभिभावक के मोबाइल पर चला जाएगा जिसमें आपकी मौजूदा लोकेशन की जानकारी होगी।

बच्चों पर टेलीविजन का बढ़ता कुप्रभाव

मुकाबलों के बहाने नयी पीढ़ी को फिल्मी-ज्ञान के विशेषज्ञ बनाने की मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति आखिर हमें किस दिशा की तरफ ले जा रही है? अपने को अति माड प्रस्तुत करते हुए बेसिर-पैर का संचालन करते संचालक इन भोले-भाले बच्चों को भला क्या सिखाना चाहते हैं? भरमाने वाले चकाचौंध भरे विज्ञापनों और फिल्मी दुनिया के बाहरी आकर्षण ने उन्हें सच्चाई से कोसों दूर ले जाकर खड़ा कर दिया है। आज हर बच्चा विज्ञापन वाला बच्चा बनना चाहता है। उसे महसूस होता है कि अगर वह हारलिक्स या बार्नवीटा पी ले तो कक्षा में अव्वल आ सकता है, लाइफबाय से नहाकर वह साइकिल प्रतियोगिता में स्थान पा सकता है। दुःख तो इस बात का है, एक ओर विज्ञापन कंपनियां अपने लुभावने शब्दों के मकड़जाल से आम नागरिक को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं तथा अपनी वस्तुओं की एक मात्र गारंटी के रूप में नारी को नग्न कर देने पर मानो तुली हुई है। बढ़ती हिंसा व अश्लीलता बढ़ती हिंसा और अश्लीलता का जो जहर वातावरण में घुल रहा है, उसकी पहुंच टीवी के माध्यम से घर-घर तक हो रही है और दर्शकों के (मुख्यतः बच्चों के) मन-मस्तिष्क दूषित हो रहे हैं। इससे कई दर्शकों का आचरण तो इस सीमा तक बिगड़ गया है कि वे क्रूर हिंसा व हत्या जैसे अपराध फिल्मों से प्रेरणा लेकर करते पाए गए हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व मद्रास उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अपराधी शंकर को उसके द्वारा एक वेश्या सहित छह लोगों की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गयी। हत्या का विचार अपराधी शंकर में फिल्म देखकर आया। अगर यह समस्या केवल सिनेमा घरों तक ही रहती तो भी ठीक था, लेकिन केवल टीवी और प्रतियोगिता की दौड़ में विदेशी टीवी कार्यक्रमों से आगे निकलने को इच्छुक टीवी कृपा के कारण हिंसा और अश्लीलता से भरे फिल्मों के दृश्य घर-घर में पहुंच गए हैं और इस तरह हिंसा और अश्लीलता से भरे दृश्यों का जहर हमारे बच्चों, किशोरों व युवाओं को लगातार पंगु बना रहा है। जबरदस्त घुसपैठ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये दृश्य बच्चों के कोमल मन-मस्तिष्क पर अत्यंत खराब प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे वे जीवन पर्यन्त मुक्त नहीं हो सकते। उल्लेखनीय है कि मन के अलावा अंतर्मन यानी अवचेतन मन भी होता है, जिसे 'सबकांशस माइंड' कहते हैं। हमारे कार्य-कलाप, हमारी गतिविधियां मन के आदेश के अनुसार होती हैं और मन के विचार जो भी विचार सुनते हैं, जो दृश्य देखते हैं, वे तत्काल हमारे अंतर्मन में प्रवेश कर जाते हैं और बार-बार हमाने मन में उनका विचार आता रहता है। नवयुवक, बच्चों और किशोरों के मन कोरी स्लेट की तरफ साफ होते हैं। अबोध और भोले-भावुक मन पर जो प्रभाव पड़ता है, वह बहुत गहरा और लम्बे समय तक असर करने वाला होता है। इसमें कोई शक नहीं कि टीवी की बदौलत पीढ़ियों का अंतर दिनों-दिन गहराता चला जा रहा है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और अब तो छोटा परिवार भी सुखी परिवार नहीं रहा। वहां टीवी की जबरदस्त घुसपैठ के भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। सीमित सदस्यों वाले उच्चवर्गीय और उच्च मध्यवर्गीय ऐसे परिवारों की आज कमी नहीं, जहां हर सदस्य के लिये अलग टीवी सेट होता है। यानी टीवी देखते-देखते भी जो आपसी संवाद की थोड़ी-बहुत संभावना थी, वह भी खत्म। बच्चे अपनी मनमर्जी से किसी भी वक्त, कोई भी चैनल और किसी भी स्तर का कोई भी कार्यक्रम देख सकते हैं। यह सर्वविदित है कि बच्चों में असीम क्षमताएं होती हैं। यदि उनके मन को संस्कारों, स्नेह, स्वाभिमान और संस्कारों से सींचा जाए तो वे अपने नाजुक पंखों से बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। सिर्फ जरूरत होती है दृढ़ इच्छाशक्ति और सही मार्गदर्शन की। ऐसे में यह चिंतन-मनन लाजिमी हो ही जाता है कि टेलीविजन बच्चों को क्या परोस रहा है? भारत की सांस्कृतिक धरोहर की, सौंदर्य संपन्नता की सराहना सारी दुनिया करती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, भारतीयों की वेश-भूषा, शाकाहारी भोजन तथा सामाजिक जीवन के शालीन रख-रखाव से पश्चिम के लोग जहां प्रभावित होते हैं, वहीं हमारे संपन्न तथा मध्यमवर्ग पर यूरोप और अमेरिका के पाप संगीत, वेश-भूषा प्रतियोगिताओं, फास्टफूड और कैसिनों की खबत सवार है।